पूर्वोत्तर भारत के विकास का ग्रोथ इंजन है: श्री अमित शाह

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 03 – अंक : 11 – फरवरी 2026

सारथियों की समृद्धि का माध्यम बनेगी

भारत टैक्सी

पूर्वोत्तर भारत के विकास का ग्रोथ इंजन है: श्री अमित शाह 20

बड़गांव कृषि सेवा सहकारी समिति ने बदली किसानों की तकदीर 29

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार जागरण
फरवरी 2026, अंक 11, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
डॉ. सुधीर महाजन
संपादक
राजीव शर्मा

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें :
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com
प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।
निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली : 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते :

MINISTRY OF COOPERATION

NCUI हाट

CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुनः उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़े प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

आवरण कथा

05
सारथियों की समृद्धि का माध्यम बनेगी भारत टैक्सी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मालिकाना हक का एक मॉडल तैयार कर रहा है।

12
आदि शंकराचार्य जी ने सनातन के मूल तत्व से जनमानस को जोड़ा : श्री अमित शाह

ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि यह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इस सृष्टि पर अब तक जितना ज्ञान उपलब्ध है, उसमें 'शिवोदृहम्' से बढ़कर कुछ नहीं है। उपनिषदों की इतनी सरल, सटीक और सत्य के निकट व्याख्या और कोई नहीं दे सकता, जो आदि शंकराचार्य ने किया है।

'नशा मुक्त भारत' की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा देश 13

गीता प्रेस ने देशवासियों के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा बढ़ाई 16

आत्मनिर्भरता से अपनी सेनाओं को आधुनिक बना रहा भारत 19

आधुनिक व आत्मनिर्भर हो रही भारतीय रेलवे : प्रधानमंत्री श्री मोदी 22

बीते 11 वर्षों में सतत विकास की परंपरा हुई स्थापित 24

शिक्षा व्यक्तिगत विकास के साथ सामाजिक जीवन के लिए भी जरूरी 26

29
बड़गांव कृषि सेवा सहकारी समिति ने बदली किसानों की तकदीर

सहकार की नई मिसाल बनेगी भारत टैक्सी

भारत में सहकारिता का निरंतर विकास और विस्तार हो रहा है। सहकारी क्षेत्र को सशक्त, समर्थ और आम जन के लिए बहुपयोगी बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सौ से अधिक सहकारी पहलों के जरिए इसे 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को पूरा करने वाले एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए तकनीकी व बुनियादी सुधार किए हैं। भारत टैक्सी का शुभारंभ भी सहकारी क्षेत्र में एक ऐसा ही पहल है जो निजी क्षेत्र के टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों के अधिकतम मुनाफा केंद्रित व्यावसायिक लक्ष्यों को दरकिनार कर सहकारी की भावना से स्थापित की गई है। टैक्सी चालकों को सशक्त बनाने और सहकारी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह सहकारी पहल की गई है, जो देश में टैक्सी सेवा के क्षेत्र में एक भविष्यलक्षी परिवर्तनकारी कदम है। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नामक बहु-राज्य सहकारी समिति के जरिए इस सहकारी पहल को आगामी तीन वर्षों में देश के सभी शहरों तक ले जाने की आकांक्षा के साथ फिलहाल दिल्ली-एनसीआर और गुजरात व महाराष्ट्र में इसका परिचालन शुरू किया गया है।

सार्वजनिक परिवहन में एक नए युग की शुरूआत करने वाले इस अभूतपूर्व पहल ने सहकरिता की नई उड़ान को पंख दे दिया है। निजी कंपनियों की तरह ऐप आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित यह पहल सहकारी मूल्यों पर आधारित समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। यह सहकारी मॉडल लाभ के समान बंटवारे और लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि प्लेटफॉर्म का लाभ सीधे इसे चलाने वालों तक पहुंचे। इस टैक्सी सेवा में सेवा प्रदाता ड्राइवरों और सवारियों, दोनों को किसी प्रकार की कोई आर्थिक क्षति नहीं होगी, क्योंकि टैक्सी ड्राइवरों ही यहां राइडर से मिलने वाले किराए का मालिक होगा और सेवा प्रदाता कंपनी को अपने लाभांश का हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, वहीं सवारी को भी निजी कंपनियों की तरह व्यस्त ट्रैफिक के समय कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। इस सहकारी संस्था के संचालन के लिए एक अंतरिम बोर्ड का गठन किया गया है, लेकिन पूरे परिचालन व्यवस्था में सदस्य टैक्सी चालकों की भागीदारी अहम होगी।

इस सेवा का शुभारंभ करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ही स्वयं सहकार टैक्सी का विचार प्रस्तावित किया था। दोपहिया, रिक्शा, टैक्सी और चार पहिया वाहनों का एक ही मंच पर पंजीकरण करने वाले इस सेवा में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि श्री शाह ने टैक्सी परिचालन का लाभ सीधे चालकों को ही मिलने का विचार दिया और इससे चालकों के आय और जीवन स्तर में सुधार होगा।

नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी) द्वारा प्रवर्तित सहकार टैक्सी को भारत की सात प्रमुख सहकारी संस्थाओं, अमूल, नैफेड, नाबार्ड, इफको, कृभको, एनडीडीबी और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) का समर्थन प्राप्त है। इन संस्थानों ने परिवहन क्षेत्र में एक टिकाऊ, समावेशी और लोकतांत्रिक मॉडल बनाने के लिए 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' के सिद्धांत के तहत मिलकर काम किया है। ऐसे में, उम्मीद ही नहीं, बल्कि विश्वास है कि सहकार टैक्सी से टैक्सी चालकों की कार्य स्थितियों, आय और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा और उपभोक्ताओं को भी किफायती, कुशल और विश्वसनीय परिवहन सेवा मिलेगी।

जय सहकार

देश का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह गरीब, अन्नदाता, युवाशक्ति और नारीशक्ति को और सशक्त करने वाला है। इससे न सिर्फ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को नई मजबूती मिलेगी और किसान भाई-बहनों की आय बढ़ेगी, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' को भी बढ़ावा मिलेगा।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

सहकारिता से बहुत सारे लोग मिलकर छोटी-छोटी पूँजी लगाकर कैसे बड़ी शुरुआत कर सकते हैं, 'भारत टैक्सी' इसका उदाहरण है। भारत टैक्सी से सरकार नहीं, सहकार, टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। चालक बहन-भाई 'भारत टैक्सी' से न सिर्फ अधिक मुनाफा कमा पाएँगे, बल्कि सम्मान के साथ इसके मालिक भी होंगे।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

जब दुनिया की रफ्तार धीमी है, तब भारत आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल स्लोडाउन के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। मजबूत नीतियां, स्थिर नेतृत्व और विकास पर फोकस, यही वजह है कि भारत आज दुनिया का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं अनुभवी मार्गदर्शन तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमितभाई शाह के कुशल नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को साकार करने की दिशा में सहकारिता क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। प्राथमिक सहकारी समितियों के विस्तार, बहुराज्यीय सहकारी समितियों के सुचारु संचालन, डेयरी क्षेत्र के सशक्तीकरण, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना और दो लाख नए पैक्स की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं।

श्री मुरलीधर मोहोल
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

भारत वैश्विक सहकारी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। दुनिया की कुल सहकारी संस्थाओं में एक-चौथाई से अधिक हिस्सेदारी के साथ भारत के सहकारी मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और भरोसा मिल रहा है। भारत की यह बढ़ती वैश्विक पहचान ग्रामीण से वैश्विक स्तर तक रोजगार सृजन, महिला सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता तथा कृषि, दुग्ध और बैंकिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समावेशी विकास की नई दिशा प्रदान कर रही है।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

देश में सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा की औपचारिक शुरुआत कर बोले श्री अमित शाह

सारथियों की समृद्धि का माध्यम बनेगी भारत टैक्सी

- सहकारिता आधारित देश की पहली टैक्सी सेवा का औपचारिक शुभारंभ
- तीन साल में देश भर में उपलब्ध होगी 'भारत टैक्सी'
- 'भारत टैक्सी' को सरकार नहीं, सहकार ने किया शुरू

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मालिकाना हक का एक मॉडल तैयार कर रहा है। तीन वर्षों में भारत टैक्सी कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामख्या तक पूरे देश में हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण और समृद्धि का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को नई दिल्ली में भारत की पहली सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' के औपचारिक शुभारंभ के दौरान व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि शायद पूरी दुनिया में पहली बार ऐसी अनूठी कंपनी अस्तित्व में आ रही है, जिसका असली मालिक कोई व्यक्ति या बाहरी कंपनी नहीं, बल्कि टैक्सी चलाने वाला सारथी (ड्राइवर) ही है। सहकार टैक्सी से जुड़ा प्रत्येक सारथी ही इस सहकारी टैक्सी समिति का सच्चा मालिक है। उन्होंने कहा कि यह भारत टैक्सी से जुड़ने वाले सारथियों के जीवन, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन लाने

वाली परिकल्पना है। यह सेवा न केवल सस्ती और सुरक्षित यात्रा देगी, बल्कि लाखों ड्राइवरों के लिए स्वरोजगार और सम्मानजनक आय का नया रास्ता खोलेगी।

इस ऐतिहासिक आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से 1200 से अधिक सारथियों की भागीदारी भारत टैक्सी के चालक सशक्तीकरण और सहकारी स्वामित्व आधारित मॉडल के प्रति उनके व्यापक समर्थन को दर्शाता है। श्री शाह ने कहा कि फिलहाल इसकी शुरुआत गुजरात के कुछ शहरों, दिल्ली और एनसीआर में हुई है, जिसे अगले तीन वर्षों से भी कम समय में हम देश के हर राज्य और हर बड़े शहर तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम भारत टैक्सी में बहुत सारी नई सेवाओं को शामिल करेंगे और इसे लगातार विस्तार देंगे। श्री शाह ने विश्वास जताया कि भारत टैक्सी का भविष्य बेहद उज्ज्वल है।

श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का मॉडल न केवल सारथियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके सम्मान, सुरक्षा और स्वामित्व को भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि जिस सहकारिता मॉडल की बात की जा रही है, वही वर्तमान समय की सबसे नई और सबसे सफल शुरुआत है। भारत टैक्सी सहकारिता क्षेत्र के लिए नए आयाम खोलने की भी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि पिछले 125 वर्षों से भारत में सहकारिता आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब सहकारी मॉडल को नए-नए क्षेत्रों में ले जाने का समय आ गया है। आने वाले समय में हम तीन-चार ऐसे क्षेत्रों में इस मॉडल को आगे बढ़ाएंगे, जहां मेहनत करने वाले व्यक्ति के पसीने और परिश्रम का फल उसी के पास रहेगा।

मातृ शक्ति को एक सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प

भारत टैक्सी 'सारथी दीदी' और 'बाइक दीदी' जैसी पहलों के माध्यम से महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रहा है। अब तक 150 से अधिक महिला ड्राइवर

'भारत टैक्सी' के लांचिंग समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का मंच पर स्वागत करते सारथी

भारत टैक्सी सारथियों की समृद्धि और खुशहाली का बनेगा जरिया

टैक्सी ड्राइवरों को प्रेरित करते हुए श्री शाह ने कहा कि अभी जहां उनकी टैक्सी किसी और की जेब में पैसे डालता है, वहीं अब टैक्सी का पहिया किसी और की कमाई के लिए नहीं, बल्कि टैक्सी सारथियों की समृद्धि और खुशहाली के लिए घूमेगा। यह विचार सहकारिता की भावना से ही जन्म लेता है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता का असली अर्थ यही है कि जब ढेर सारे छोटे-छोटे पूंजी वाले लोग अपनी ताकत को एकत्रित कर लेते हैं, तो वे मिलकर बहुत बड़े-बड़े काम कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी होती है, वे अकेले बड़ा काम करते हैं और मुनाफा भी कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है। भारतीय संसद में जब पहली बार श्री शाह ने कोऑपरेटिव टैक्सी का जिक्र किया तो बहुत सारे लोगों, जिन्हें 'सहकार' और 'सरकार' के बीच का भेद नहीं मालूम है, ने यह पूछा कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में क्यों प्रवेश कर रही है। श्री शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार नहीं, बल्कि सहकार (कोऑपरेटिव) टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। भारत टैक्सी की कल्पना मौजूदा तीनों प्रकार के टैक्सी वाहनों को एक साथ जोड़कर की गई है जिसमें चार पहिया टैक्सी, तीन पहिया और दो पहिया वाहन शामिल हैं। दिल्ली-एनसीआर के सभी ग्राहकों और सारथियों को श्री शाह ने संदेश दिया कि भारत टैक्सी उनकी सेवा में पूरी तरह शुरू हो रही है। यह सिर्फ एक टैक्सी सेवा नहीं है, बल्कि हमारे देश के करोड़ों सारथियों की समृद्धि, आत्मसम्मान और आर्थिक मजबूती बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनने जा रही है।

स्वामित्व मॉडल पर आधारित टैक्सी को देश में पहली बार लॉन्च किया गया है, जो न केवल सारथियों के लिए मालिकाना हक की भावना लाता है, बल्कि यात्रियों और विभिन्न संस्थाओं के लिए भी एक भरोसेमंद और सुविधाजनक विकल्प प्रस्तुत करता है।

प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। श्री शाह ने देश की मातृ शक्ति को संदेश दिया कि भारत टैक्सी उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगी। श्री शाह ने कहा कि हमने सारथी दीदी की एक खास संकल्पना तैयार की है जिसके तहत आने वाले समय में ऐप में 'सारथी दीदी' के लिए एक अलग विंडो होगी और इसके जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली किसी भी महिला को केवल 'सारथी दीदी' ही लेने आएंगी। उन्होंने कहा 'सारथी दीदी' दो पहिया वाहन लेकर आएंगी और बहुत कम किराए में सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाएंगी। यह सुविधा महिलाओं के लिए बहुत बड़ी और व्यावहारिक राहत साबित होगी। आने वाले दिनों में सारथी दीदी के माध्यम से देश की मातृ शक्ति को एक सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। यह सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इंश्योरेंस, लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा

आने वाले दिनों में हमारे सारथी भाइयों-बहनों को इंश्योरेंस, सरकारी रोजगार योजनाओं, लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ स्वतः मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है, जिससे हर सारथी को पूरा सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती मिल सके। वहीं, सारथियों को उनके दायित्वों के प्रति सचेत करते हुए श्री शाह ने कहा कि ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपनी टैक्सी की गुडविल बनाए रखें और सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि शिकायतों की सुनवाई के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और निष्पक्ष सुनवाई के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।

सारा मुनाफा भारत टैक्सी से जुड़े सारथी के अकाउंट में जाएगा

सहकार टैक्सी कुल मुनाफे में सिर्फ 20 फीसदी पैसे ही अपने पास रखेगी। सारा मुनाफा भारत टैक्सी से जुड़े सारथी के अकाउंट में ही जाएगा। भारत टैक्सी के पूंजी खाते में पड़े 20 रुपए के मालिक भी सारथी ही होंगे। हर पांच साल पर होने वाले चुनाव के बाद टैक्सी सारथियों के चुने गए दो प्रतिनिधि बोर्ड में बैठेंगे, जो उनके हितों की देखभाल करेंगे और उनके लिए फैसले करेंगे। यही सहकारिता की आत्मा और सच्चे मालिकाना हक की भावना है। भारत टैक्सी द्वारा तय किया गया फिक्स्ड चार्ज सारथियों के अकाउंट से अलग रहेगा। इसके अलावा, भारत टैक्सी सारथियों की पसीने की कमाई से एक प्रतिशत भी कमीशन नहीं काटेगी, जिससे उनकी समृद्धि तेजी से बढ़ेगी। भारत टैक्सी का उद्देश्य कंपनी की पूंजी को बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत टैक्सी के असली मालिक, सारथी भाइयों और सारथी दीदियों, का मुनाफा और आय बढ़ाना है। किसी भी सारथी का अकाउंट बिना उचित सुनवाई के बंद नहीं किया जाएगा। ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान सीधे सारथी के अकाउंट में तत्काल ऑटोमैटिक ढ़ंग से ट्रांसफर हो जाएगा और इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

श्री शाह ने तंज के अंदाज में कहा कि अब तक बुकिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस और भारी कमीशन जैसी बातें कंपनी की बैलेंस शीट को मोटा करती थीं और सारथी की कमाई को घटाती थीं। भारत टैक्सी में ऐसी कोई फीस या कमीशन की व्यवस्था ही नहीं है और सारथी ही मालिक होंगे। उन्होंने कहा कि यह विचार पश्चिमी सोच वाले लोगों को शायद समझ में न आए, लेकिन यही सहकारिता की असली ताकत है।

श्री शाह ने कहा कि सारथी छुपे अतिरिक्त चार्ज से पूरी तरह मुक्त हैं, क्योंकि ऐसा चार्ज लेना सारथी के साथ एक तरह का छल है। टोल, पार्किंग और अन्य सभी तरह के अतिरिक्त शुल्क से भी मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही हर समय 24 घंटे हेल्पलाइन सारथियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी।

देश में पहले से ही कई विश्व-स्तरीय सफल सहकारी मॉडल

देश में पहले से ही कई ऐसे विश्व-स्तरीय सफल सहकारी मॉडल खड़े हो चुके हैं, जिनमें अमूल, इफको और कृभको जैसी संस्थाएं शामिल हैं। वैश्विक शिखर पर ख्याति अर्जित कर रहे अमूल का उदाहरण देते हुए श्री शाह ने कहा कि सिर्फ 11 दूध उत्पादकों ने अमूल की शुरुआत की थी, जहां आज गुजरात में 36 लाख से अधिक पशुपालक महिलाओं का विशाल वटवृक्ष खड़ा हो चुका है। ये पशुपालक महिलाएं सवा लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करती हैं और इस सहकारी मॉडल

से यह स्वयं सिद्ध होता है कि आम लोगों की छोटी शुरुआत भी बहुत बड़े परिणाम दे सकती है। उन्होंने कहा कि पशुपालक बहनें दूध बेचकर एक करोड़ रुपए तक की सालाना कमाई कर रही हैं, जो सहकारी मॉडल का कमाल है। सहकारी संस्था में शुरुआती पूंजी बहुत बड़ी नहीं थी। इसी तरह सहकार टैक्सी के सदस्य ड्राइवरों की शेयर पूंजी सिर्फ 500 रुपए निर्धारित है। यही प्रावधान सारथियों (ड्राइवर) को असली मालिक का दर्जा दे रहा है। यह छोटी सी राशि टैक्सी सारथियों की मेहनत, आत्मसम्मान और उनकी आर्थिक आजादी की नींव बनने जा रही है।

स्वामित्व, सुरक्षा, सम्मान और सबकी प्रगति भारत टैक्सी के मूल मंत्र

भारत टैक्सी के चार मूल मंत्र हैं—स्वामित्व, सुरक्षा कवच, सम्मान और सबकी प्रगति के लिए लाभांश का उचित वितरण। इन्हीं चार उद्देश्यों के साथ भारत टैक्सी की शुरुआत हुई है और आने वाले समय में यह एक बहुत सफल प्रयोग साबित होगा। 6 जून 2025 को इसकी स्थापना से लेकर और व्यावसायिक लॉन्चिंग के महज इन आठ महीनों के भीतर दिल्ली और गुजरात में किसी भी अन्य टैक्सी कंपनी से ज्यादा सारथी और ग्राहक भारत टैक्सी से जुड़ चुके हैं। इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन किसी अन्य कंपनी ने नहीं कराए हैं।

सभी सारथी आसानी से करा सकते हैं ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन

केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की थी। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में देश भर के सवा करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स के लिए ढेर सारी योजनाओं और सुविधाओं का विस्तार किया है। पहले जहां ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अधिकार केवल उन लोगों को था जिनकी पेंशन कटती थी या जो औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त श्रमिक के रूप में पंजीकृत थे, वहीं अब इस सीमा को हटा दिया गया है। इससे देश के सवा करोड़ गिग वर्कर अब ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी से जुड़े सभी सारथी अब आसानी से ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अपने और अपने परिवार के लिए स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। भारत टैक्सी से जुड़ते ही सारथियों को यह मुफ्त चिकित्सा सुविधा

- भारत टैक्सी की 'सारथी दीदी' की सुविधा महिलाओं को सुरक्षा और सारथी दीदियों को सम्मान व आत्मनिर्भरता देगी
- इसके चार मूल विचार हैं- स्वामित्व, सुरक्षा कवच, सम्मान और लाभांश का समान वितरण
- भारत टैक्सी के आते ही बड़ी कंपनियों ने अपने कमीशन कम कर ड्राइवरों और यात्रियों को डिस्काउंट देना शुरू किया
- सारथियों को पांच लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, बीमा, सस्ते लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा
- भारत टैक्सी का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट अथारिटी और एसबीआई सहित नौ प्रमुख संस्थानों के साथ हुआ एमओयू

मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध अन्य कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी भारत टैक्सी के सारथियों के लिए अपने आप सक्रिय हो जाएंगी।

भारत टैक्सी के ऐप में आपातकालीन अलर्ट सुविधा

भारत टैक्सी के ऐप में संकट के समय आपातकालीन अलर्ट की सुविधा दी गई है। इसके माध्यम से आपातकालीन स्थिति में तुरंत सुरक्षा और सहायता प्राप्त की जा सकती है। अभी दिल्ली-एनसीआर में आठ हेल्पलाइन और सहायता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और आने वाले समय में देशभर में ऐसे केन्द्रों का एक व्यापक जाल बिछाया जाएगा। शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया ऐप के माध्यम से, वेबसाइट पर और टोल-फ्री नंबर के जरिए तीन स्तरों पर संचालित होगी। इसके साथ ही सहकारी प्रतिनिधि नियमित रूप से सारथियों के साथ बैठकें करेंगे, जिससे कि हर समस्या का समय पर समाधान हो सकेगा। ■

सहकारिता का साथ मिला तो दौड़ पड़ी भारत टैक्सी, सारथी हुए खुश

सबसे पहले तो मैं भारत टैक्सी को धन्यवाद देता हूं। पहले मैं अपना काम करता था जिसमें बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद मैं भारत टैक्सी से जुड़ा जिससे मेरा बहुत अच्छा काम हुआ। दूसरी कंपनियों और भारत टैक्सी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसका मालिक खुद सारथी (ड्राइवर) भाई हैं। उसमें (दूसरी कंपनियां) मालिक नहीं बल्कि कमीशन बेस्ड था। भारत टैक्सी में सारा फायदा सारथी की जेब में जा रहा है। ग्राहकों के लिए भी यह बहुत अच्छा है। अच्छा प्रदर्शन करने पर यहां प्रोत्साहन मिलता है। बाकी लोगों को भी इससे लाभ मिल रहा है। स्वदेशी टैक्सी प्लेटफार्म है। इससे होने वाली कमाई देश में ही रहेगी। ज्यादा से ज्यादा सारथी भाइयों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए।

धर्मेंद्र कुमार, गाजियाबाद

बिहार की रहने वाली हूं। पति की मौत के बाद मैं सिंगल ओमेन मदर हूं। सीढ़ियों से गिरने से मेरी हड्डियां टूट गई थीं, जिससे मैं कोई और कामकाज नहीं कर सकती थी। लेकिन मैंने ड्राइविंग सीखकर टैक्सी चलाने का फैसला किया। इसीलिए बच्चों के पालन पोषण के लिए मैंने बैंक से लोन लेकर एक कैब लेकर चलानी शुरू कर दी थी। इसी बीच भारत टैक्सी के आने के बाद मुझे बड़ा सहारा मिल गया। अब मेरी अच्छी कमाई हो जाती है। महिला सवारियां बहुत खुश होती हैं। ड्राइवरों को भी फायदा होता है। महिला ड्राइवरों को इसमें प्राथमिकता मिलती है। भारत टैक्सी के साथ कैब ड्राइवर बनने में काफी फायदा मिला है।

नीलम शर्मा, दिल्ली

मैं घनश्याम गौतम सुभाष नगर में रहता हूं। मैं पहले बिजनेश करता था, लेकिन वहां नुकसान होने लगा तो उसे छोड़कर मैंने एक टैक्सी खरीद ली और बाजार में सक्रिय टैक्सी कंपनियों से जुड़ गया। इसी बीच मुझे भारत टैक्सी के बारे में पता चला और मैं इससे जुड़ गया। मैं इसमें सहकार दूत भी हूं। मैंने अपने मित्र ड्राइवरों को इससे जोड़ा है। इसकी सेवा लेने के लिए कस्टमर को प्रेरित करता रहता हूं। एक बार हमारी गाड़ी में आग लग गई। इसके बारे में जब भारत टैक्सी के पदाधिकारियों को पता चला तो वे मेरे साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और आपकी हरसंभव मदद की जाएगी। जबकि अन्य कंपनियां दुर्घटना आदि की स्थिति में साथ छोड़ देती हैं और ऐप से हटा देती हैं।

घनश्याम गौतम, दिल्ली

मेरा नाम उनराज कटवी है। मैं अहमदाबाद, गुजरात से आया हूं। मैं देश के सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वे भारत टैक्सी से जुड़ें और इसे अपनाएं। क्योंकि यह अपना है। अभी तक इस क्षेत्र में सक्रिय अन्य कंपनियां ड्राइवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। इसीलिए हमने भारत टैक्सी से जुड़ना उचित समझा। क्योंकि यह सहकारिता मॉडल पर आधारित है और इसमें किसी भी साथी ड्राइवर (सारथी) को कमीशन के नाम पर तंग नहीं किया जाता है। मैं सहकारिता के गढ़ गुजरात से आता हूं। वहां की अमूल सहकारी कंपनी से पूरी दुनिया परिचित है। इसलिए गुजरात के लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भारत टैक्सी की खास बात यह है कि इसमें ड्राइवरों को सारथी नाम दिया गया है। यह हमारे लिए सम्मान की बात है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे।

उनराज कटवी, गुजरात

भारत टैक्सी के सभी सारथी भाइयों को नमस्कार और उनके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। भारत टैक्सी सहकारिता के माध्यम से चलाया हुआ प्लेटफार्म है। हम सब ड्राइवर भाइयों के लिए यह सुनहरा मौका है। यहां कमीशन के नाम पर कुछ भी नहीं लिया जाता है। बल्कि भारत टैक्सी के कारोबार में होने वाले लाभ में सारथी भाइयों की हिस्सेदारी मिलेगी। वर्ष के आखिर में भारत टैक्सी सभी सहयोगियों को लाभांश देगी। इसको सफल बनाना है। दूसरी जगहों पर 15-15 घंटे गाड़ी चलाने पर भी कुछ नहीं बचता था, लेकिन इसमें हमारी कमाई का पूरा का पूरा मिलने वाला है। इसमें और भी बहुत सारी सहूलियतें दी जा रही हैं। हम सभी सारथी भाइयों से आग्रह करेंगे कि भारत टैक्सी प्लेटफार्म के माध्यम से गाड़ी चलाएं।

धर्मेंद्र वर्मा, दिल्ली

मुझे बहुत खुशी मिल रही है। भारत टैक्सी से हमारा और हमारे परिवार का भविष्य जुड़ रहा है। इसकी कमाई से सीधे हमारे पास ही आएगी। इसमें सेफ्टी और भविष्य की सुरक्षा भी मिल रही है। भारत टैक्सी की लांचिंग के साथ मूलभूत सुविधाएं ड्राइवरों को मिल रही है। हमे पूरी बचत होगी जिससे हम गाडी का अच्छी तरह रखरखाव कर सकेंगे। घर परिवार अच्छी तरह चला पाएंगे। दूसरी कंपनियों के साथ जुड़ना हमारी मजबूरी बन गया था लेकिन आज स्वदेशी भारत टैक्सी ने सुनहरा अवसर दिया है, जिससे हमारे ड्राइवरों का भविष्य मजबूत होगा।

अवतार सिंह, दिल्ली

भारत टैक्सी से जुड़कर बहुत खुशी महसूस हो रही है। भारत टैक्सी ऐप में महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान का बहुत ध्यान रखा गया है। इस योजना में एक खास बात यह है कि अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए ऐप में एक दूरभाष नंबर दिया गया है। इस नंबर पर फोन कर हम अपनी समस्या के बारे में संबधित व्यक्ति से सीधे बात कर सकते हैं। इससे हमें अपनी समस्या को रखने में काफी सहूलियत हो गई है, जबकि अन्य दूसरे प्लेटफार्मों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।

अनुपमा, दिल्ली

मैं वीरेंद्र सिंह दिल्ली से हूं। सन 1990 से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि माननीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी स्वदेशी भारत टैक्सी को लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जिन टैक्सी कंपनियों से जुड़े थे, वहां 8 से 18 घंटे काम करके भी हम अपने परिवार का पालन-पोषण ढंग से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब अपनी इस स्वदेशी भारत टैक्सी कंपनी से हमें बहुत उम्मीदें हैं। क्योंकि अब हमें किसी को कोई कमीशन नहीं देना है। हम जो कमाएंगे, सब हमारा होगा। इसलिए सभी सारथी भाइयों को इससे जुड़ना चाहिए। माननीय श्री अमित शाह जी के पहल का न केवल हमें, बल्कि हमारी पीढ़ियों को भी लाभ होगा। हम उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं।

वीरेंद्र सिंह, दिल्ली

भारत टैक्सी ने प्रमुख संस्थाओं के साथ किया समझौता

सहकार जागरण टीम

- रोजगार, मोबिलिटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी भारत टैक्सी
- दिल्ली-एनसीआर में 2.5 लाख सारथी और 8.5 लाख से ज्यादा यात्री इस टैक्सी सेवा से जुड़े
- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मालिकाना हक का अनूठा मॉडल तैयार
- भारत टैक्सी का उद्देश्य सारथियों को उनके मुनाफे का मालिक बनाकर उनकी आय बढ़ाना है

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इफको टोक्यो इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कुल नौ अग्रणी सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं के साथ भारत टैक्सी ने भागीदारी समझौता (एमओयू) किया है। इसका उद्देश्य परिचालन एकीकरण, डिजिटल सक्षमता तथा सेवा गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है। इन समझौतों के जरिए भारत टैक्सी के ग्राहकों को कई अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही इन सभी संस्थाओं को भारत टैक्सी की सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। ये संस्थाएं अब सहकार टैक्सी की सफलता में हिस्सेदार बन चुकी हैं।

दिल्ली 'भारत टैक्सी' के सहकारी कैब मॉडल से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ एमओयू पहल का उद्देश्य दिल्ली में सुरक्षित, भरोसेमंद और पारदर्शी टैक्सी सेवाओं को मजबूत करना है। टैक्सी चालकों को सॉफ्ट स्किल्स तथा दिल्ली की संस्कृति, इतिहास और विरासत का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे दिल्ली पर्यटन के ब्रांड एंबेसडर के रूप में कार्य करेंगे। सहकारी मॉडल के तहत सारथी अपनी कमाई का

बड़ा हिस्सा स्वयं रख पाएंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

इसके तहत भारत टैक्सी को दिल्ली में 21 स्थानों पर स्थित 34 प्री-पेड टैक्सी बूथों के डिजिटल संचालन की अनुमति मिलेगी, जिससे यात्री सुरक्षा, पारदर्शिता, चालक आय और सेवा गुणवत्ता में वृद्धि होगी। दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से भारत टैक्सी ने एक संयुक्त कमांड एवं कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया है, जिसमें रीयल-टाइम राइड मॉनिटरिंग, एसओएस अलर्ट और त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र शामिल हैं, जो सड़क सुरक्षा, नियामक अनुपालन और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देंगे।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनइजीडी) के साथ गए समझौता ज्ञापन के तहत डिजिटल इंडिया ढांचे के अंतर्गत भारत टैक्सी को परामर्श एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे डिजी लॉकर, उमंग और एपीआई सेतु के साथ एकीकरण संभव होगा। इससे सारथियों को पेपरलेस ऑनबोर्डिंग, सरकारी सेवाओं तक एकीकृत पहुंच, सुरक्षित इंटरऑपरेबल संचालन, कैशलेस भुगतान और बेहतर परिचालन दक्षता का लाभ मिलेगा।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के साथ साझेदारी के तहत 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर बाइक टैक्सी, ई-ऑटो एवं सीएनजी ऑटो और कैब के माध्यम से अंतिम-मील कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके जरिए यात्री एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरे सफर की योजना और भुगतान कर सकेंगे और चालकों को अधिक ट्रिप्स और कम निष्क्रिय समय का लाभ मिलेगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ किया गया एएमओयू देशभर के एएआई हवाई अड्डों पर भारत टैक्सी के संचालन को नियंत्रित करेगा, जिसमें पिक-अप जोन, साइनज की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा एवं सेवा मानक निर्धारित किए गए हैं। इससे पूरे भारत में विनियमित हवाई अड्डा संचालन संभव होगा।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम व दिल्ली एयरपोर्ट पार्किंग सर्विसेज के साथ हुए समझौते के तहत इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनलों पर कई पार्किंग स्थानों पर भारत टैक्सी की व्हाइट कैब सेवाओं को अनुमति दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पार्किंग सर्विसेज पहले वर्ष के लिए प्रति ट्रिप 245 रुपए के पिक-अप शुल्क पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगा। इससे भारत टैक्सी की एयरपोर्ट राइड्स की संख्या और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

इफको-टोकियो इंश्योरेंस को भारत टैक्सी के बीमा भागीदार के रूप में जोड़ा गया है, जो नाममात्र दरों पर चालकों को पांच लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करेगा। साथ ही यह सारथी कल्याण एवं बीमा समाधानों पर दीर्घकालिक परामर्श सहयोग भी प्रदान करेगा।

पेटीएम के साथ एमओयू भारत टैक्सी को डिजिटल भुगतान, को-ब्रांडेड ऑफरिंग्स तथा फिनटेक सक्षमता प्रदान करेगा। इसमें पेमेंट गेटवे एकीकरण और पेटीएम के पार्टनर इकोसिस्टम तक पहुंच शामिल है। पेटीएम पारिवारिक कवरेज सहित सारथी समूह को स्वास्थ्य बीमा में भी सहयोग कर रहा है।

जीएमआर के साथ साझेदारी एयरपोर्ट मोबिलिटी संचालन को और सुदृढ़ करते हुए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनलों पर भारत टैक्सी की विनियमित पहुंच और सेवा विस्तार को मजबूती प्रदान करेगी।

एसबीआई के साथ हुए एमओयू के जरिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के अंतर्गत वाणिज्यिक यात्री वाहनों के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। सहकार टैक्सी पात्र चालक-मालिकों की पहचान और सहायता करेगा, जबकि एसबीआई अपनी प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप शीघ्र विचार सुनिश्चित करेगा।■

भारत टैक्सी ने उड़ाई अन्य टैक्सी संचालकों की नींद

सहकार जागरण टीम

सहकारिता क्षेत्र की चर्चित भारत टैक्सी की लांचिंग ने अन्य टैक्सी संचालकों की नींद उड़ा दी है। भारत टैक्सी प्लेटफार्म से जुड़े सारथियों (ड्राइवरों) को मिल रही विभिन्न सहूलियतों से दूसरी कंपनियों में घबराहट का माहौल है। भारत टैक्सी के ड्राइवरों को जहां बिना कमीशन काटे पूरा का पूरा किराया मिलता है, वहीं अन्य टैक्सी कंपनियां भारी कमीशन काटती है, जिससे ड्राइवरों को नुकसान होता है। भारत टैक्सी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अब अन्य कंपनियां ड्राइवरों और सवारियों को कई तरह के प्रलोभन देने में जुट गई हैं। जहां किराये में कटौती

कर सवारियों को लुभा रही हैं वहीं ड्राइवरों के लिए कूपन की घोषणा की जा रही है। भारत टैक्सी के दबाव में पहले से चल रही टैक्सी प्लेटफार्म ड्राइवरों (सारथी) के लिए आकर्षक तोहफा भी दे रही हैं। भारत भारत टैक्सी की लांचिंग के बाद अब तक पौने चार लाख से अधिक ड्राइवरों ने इस प्लेटफार्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जो अपने आप एक रिकार्ड है। जबकि लगभग 22 लाख ग्राहकों ने भारत टैक्सी ऐप को डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें रोजाना वृद्धि हो रही है।■

नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की नौवीं शीर्ष स्तरीय बैठक में बोले श्री अमित शाह

'नशा मुक्त भारत' की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा देश

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी की शताब्दी के समय भारत को पूरे विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे भारत की रचना करने के लिए हम सब का यह दायित्व है कि हम युवा पीढ़ी को ड्रग्स से संपूर्ण सुरक्षा दें। देश की अगली पीढ़ियों को बचाने का काम हम शीर्ष प्राथमिकता के साथ करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को नई दिल्ली के के विज्ञान भवन में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की नौवीं शीर्ष स्तरीय बैठक के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने नशे के खिलाफ लड़ाई में काफी सफलता प्राप्त की है। देश में ड्रग्स के खिलाफ तीन साल तक चलने वाला देशव्यापी अभियान शुरू होने जा रहा है। हमें 'नशा मुक्त भारत' बनाना है और देश के युवाओं को ड्रग्स से सुरक्षित करना है।

देश में मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे सामूहिक राष्ट्रीय प्रयासों की समीक्षा करते हुए श्री शाह ने देश में मादक पदार्थों के नेटवर्क और गिरोहों को खत्म करने के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण, गुप्त जाल से जुड़ी चुनौतियों, व्यापक जांच और पूर्वनिर्धारित पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम पर विशेष जोर दिया और कहा कि अब हमने स्पीड बना ली है और तीन सूत्रीय प्लान ऑफ एक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, 'हम ड्रग्स की सप्लाई चेन के प्रति सामूहिक रूथलैस अप्रोच, डिमांड रिडक्शन के प्रति स्ट्रेटेजिक अप्रोच और हार्म रिडक्शन के लिए ह्यूमन अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, तभी नशामुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।' सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि ड्रग्स बनाने और बेचने वालों के प्रति कोई दया नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिसने नशे का सेवन शुरू किया है, उसके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

नार्कोटिक्स के विरूद्ध लड़ाई में सरकार की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जहां 2004 से 2013 के दौरान 40 हजार करोड़ रुपए मूल्य का 26 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया, वहीं पिछले 11 वर्षों में हमने एक लाख 71 हजार करोड़ रुपए मूल्य की एक करोड़ 11 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है। सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ हमारी मुहिम उत्साह देने वाली रही है। ड्रग्स को नष्ट करने में भी 11 गुना बढ़ोत्तरी हुई है और अब तक 40 हजार एकड़ भूमि पर अफीम को नष्ट किया गया है। 31 मार्च, 2026 से नशे की इस समस्या के खिलाफ देश में तीन साल का एक सामूहिक अभियान शुरू हो रहा है।■

अहमदाबाद में गुजराती भाषा में प्रकाशित आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली का विमोचन

आदि शंकराचार्य जी ने सनातन के मूल तत्व से जनमानस को जोड़ा : श्री अमित शाह

सहकार जागरण टीम

ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि यह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इस सृष्टि पर अब तक जितना ज्ञान उपलब्ध है, उसमें 'शिवोदृहम्' से बढ़कर कुछ नहीं है। उपनिषदों की इतनी सरल, सटीक और सत्य के निकट व्याख्या और कोई नहीं दे सकता, जो आदि शंकराचार्य ने किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को अहमदाबाद में गुजराती भाषा में प्रकाशित आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली के विमोचन के दौरान व्यक्त किया। 'सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट' के द्वारा आदिशंकर रचित ज्ञानसागर के गुजराती भाषा में प्रकाशित होने पर खुशी जताते हुए श्री शाह ने कहा कि स्थानीय भाषा में प्रकाशित आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली गुजरात के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। आदि शंकराचार्य जी के ज्ञानसागर और इन 24 पुस्तकों के प्रकाशन का निश्चय ही युवाओं के जीवन एवं कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

श्री शाह ने कहा कि आदि शंकराचार्य जी ने ऐसी परंपरा स्थापित की जिससे युगों-युगों तक सनातन की सेवा की जाती रहे। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित ग्रंथ 'विवेकचूड़ामणि' एक बार अवश्य पढ़ें। इस ग्रंथ का गुजराती अनुवाद और भावानुवाद उपलब्ध होने से अब युवाओं को बड़ी सहुलियत होगी। श्री शाह ने कहा कि आदि शंकराचार्य जी ने केवल विचार ही नहीं दिया, बल्कि इसके साथ-साथ भारत को संयोजन भी प्रदान किया, सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि ज्ञान का आकार भी दिया और सिर्फ मोक्ष का विचार नहीं दिया, बल्कि मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग भी बताया। इतनी अल्प आयु में कई बार देश की पदयात्रा कर आदि शंकर ने एक प्रकार से उस जमाने में पैदल चलते विश्वविद्यालय की भूमिका निभाई और बल्कि भारत की पहचान को प्रस्तुत किया। उन्होंने चारों दिशाओं में चार मठ स्थापित किए और पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण में सनातन की ध्वजा फहराकर ज्ञानदीप की स्थापना की, जहां सारे वेदों और उपनिषदों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमेशा के लिए एक व्यवस्था स्थापित की गई।

सनातन संस्कृति के लिए संगठन का निर्माण

श्री शाह ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में सनातन धर्म कालबा' न हो, इसके लिए अखाड़ों की स्थापना की और सनातन संस्कृति के लिए संगठन का निर्माण किया। भक्ति, कर्म और ज्ञान, तीनों मार्गों से मोक्ष संभव है, यह समन्वित विचार आदि शंकराचार्य की महान देन है। शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित कर उन्होंने संवाद से समाधान और वाद-विवाद की संस्कृति की नींव रखी और प्रकृति की पूजा से लेकर सनातन के मूल तत्व को पहचानने का रास्ता आम लोगों के लिए प्रशस्त किया।

सामूहिक चरित्र निर्माण में स्वामी अखंडानंद का अहम योगदान

श्री शाह ने कहा कि गुजरात के सामूहिक चरित्र निर्माण में स्वामी अखंडानंद का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत, रामायण, योग वशिष्ठ, स्वामी रामतीर्थ के उपदेश, रामकथामृत और नीति विषयक अनेकानेक ग्रंथों को बहुत सरल तरीके से युवाओं तक पहुंचाया। आयुर्वेद, सनातन धर्म और उच्च विचारों को प्रस्तुत करने वाले साहित्य के जरिए स्वामी अखंडानंद जी ने अनेक ऋषि-मुनियों के कथनों और बोधकथाओं के माध्यम से सनातन धर्म के सार को गुजराती में प्रस्तुत किया। गुजरात के युवाओं को किफायती दामों में उत्कृष्ट साहित्य रचनाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने 'सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट' के रूप में एक बड़ी संस्था स्थापित की, जिसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र सहित अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों को गुजराती भाषा में उपलब्ध कराया है।■

एनसीसी की वार्षिक रैली में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

युवाओं के लिए बढ़े रोजगार के वैश्विक अवसर

- लाखों युवाओं के लिए अनगिनत अवसर पैदा कर रहे विभिन्न देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते
- मेहनती और उत्कृष्ट पेशेवर भारतीय युवाओं की दुनिया में हो रही बहुत मांग
- विकसित भारत के लिए नागरिक के रूप में हमें अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए

सहकार जागरण टीम

आज का युग भारत के युवाओं के लिए अवसरों का सबसे बड़ा युग है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि युवा इस दौर का सबसे ज्यादा लाभ उठाएं। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए कही। यूरोपीय संघ, ओमान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के साथ हुए भारत के मुक्त व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे लाखों युवाओं के लिए अनगिनत अवसर पैदा हो रहे हैं। पूरी दुनिया भारत के युवाओं पर बहुत भरोसा करती है। इस भरोसे का कारण देश के युवाओं का कौशल और उनके मूल्य हैं। भारतीय युवा लोकतंत्र, विविधता के प्रति सम्मान और विश्व को एक परिवार मानने जैसे मूल्यों को अपने साथ रखते हैं। इसलिए वे जहां भी जाते हैं, वहां के लोगों के साथ आसानी से घुलमिल जाते हैं और उन देशों के विकास में योगदान देते हैं। ये मूल्य भारत की संस्कृति और प्रकृति हैं।

भारत के युवाओं को मेहनती और उत्कृष्ट पेशेवर बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी खूबी के कारण युवाओं की दुनिया में बहुत मांग है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं। भारतीय डॉक्टर और इंजीनियर कई देशों में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे हैं। विदेशों में गए भारतीय शिक्षकों ने विश्वभर के समाजों में नए मूल्य जोड़े। भारतीय युवाओं के वैश्विक योगदान के साथ-साथ देश के भीतर उनकी उपलब्धियों की भी वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है। इन्हीं युवाओं की बदौलत भारत विश्व स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी की रीढ़ बन गया है। उनकी ताकत स्टार्टअप, अंतरिक्ष, डिजिटल प्रौद्योगिकी और हर क्षेत्र में क्रांति ला रही है।

यूरोपीय संघ के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहे जाने की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने इसे वैश्विक परिदृश्य में बदलाव लाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह मुक्त व्यापार समझौता विश्व की एक चौथाई जीडीपी और वैश्विक व्यापार का एक तिहाई हिस्सा है और वास्तव में भारत के युवाओं के लिए 'आकांक्षाओं को साकार करने की आजादी' है। 27 देशों के साथ हुआ यह समझौता भारतीय स्टार्टअप्स को वित्तपोषण और

नवाचार तंत्र तक आसान पहुंच प्रदान करके सहायता पहुंचाएगा, साथ ही फिल्म, गेमिंग, फैशन, डिजिटल कंटेंट, संगीत और डिजाइन के क्षेत्र में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। यह समझौता अनुसंधान, शिक्षा, आईटी और पेशेवर सेवाओं में भारतीय युवाओं के लिए नए अवसर भी पैदा करेगा। इस समझौते को इसके व्यापक लाभों के कारण 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है और इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार मिलेगी तथा 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के संकल्प को भी मजबूती मिलेगी। इस समझौते के तहत भारत के 99 प्रतिशत से अधिक निर्यात पर शुल्क या तो शून्य होगा या बहुत कम होगा। इससे कपड़ा, चमड़ा, रत्न व आभूषण, जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद और लघु एवं मध्यम उद्यमों जैसे उद्योगों को लाभ होगा। बुनकरों, कारीगरों और लघु उद्यमियों को 27 यूरोपीय देशों के विशाल बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी।

इस समझौते से भारत में अधिक निवेश आने और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, फार्मा व अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में नए संयंत्र स्थापित होने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे कृषि, खां प्रसंस्करण और मत्स्य पालन के लिए बाजार तैयार होंगे, जो किसानों, मछुआरों और ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा। यह मुक्त व्यापार समझौता भारत के युवाओं को यूरोप के रोजगार बाजार से सीधे जोड़ता है। इससे विशेष रूप से इंजीनियरिंग, हरित प्रौद्योगिकी, डिजाइन, रसद और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में अवसर पैदा होते हैं। भारतीय युवाओं के लिए 27 देशों में नए रास्ते खुल रहे हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की शक्ति व सशस्त्र बलों के शौर्य को पुनः स्थापित किए जाने और स्वदेशी हथियारों की प्रगति को प्रदर्शित करने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक युद्ध में युवाओं के कौशल की भूमिका में काफी तब्दीलियां आई है, क्योंकि अब युद्ध केवल टैंकों और तोपों से ही नहीं, बल्कि कोड और क्लाउड के जरिए भी लड़े जाते हैं। प्रौद्योगिकी में पिछड़े राष्ट्र न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी कमजोर हैं। युवाओं द्वारा किए गए नवाचार देशभक्ति को मजबूत करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देते हैं। रक्षा स्टार्टअप्स में तेजी से विकास, मेड इन इंडिया ड्रोन के विकास और एआई तथा रक्षा नवाचारों द्वारा बलों के आधुनिकीकरण के साथ सशस्त्र बलों में प्रौद्योगिकी-प्रेमी और नवोन्मेषी युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं।

स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक विकसित भारत केवल आर्थिक समृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने नागरिकों के आचरण पर भी निर्भर करता है, जिन्हें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह अभियान सरकार ने शुरू किया था, लेकिन इसे नागरिकों, युवाओं और बच्चों ने आगे बढ़ाया। इसने ये साबित किया कि स्वच्छता एक आदत, एक जीवनशैली और एक मूल्य है। नागरिक कर्तव्य की भावना दैनिक जीवन का हिस्सा बननी चाहिए और जिस प्रकार लोग अपने आंगन को सुंदर बनाना चाहते हैं, उसी भावना से उन्हें अपने शहरों को भी सुंदर बनाना चाहिए। युवाओं को हर सप्ताह कम से कम एक घंटा स्वच्छता अभियान के लिए समर्पित करना चाहिए।

युवा शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तम स्वास्थ्य बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि फिटनेस कुछ मिनटों के व्यायाम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जानी चाहिए। इसमें खान-पान से लेकर दैनिक दिनचर्या तक अनुशासित जीवनशैली शामिल हो। युवाओं में बढ़ रहे मोटापे का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अध्ययन बताते हैं कि भारत में हर तीन में से एक व्यक्ति भविष्य में मोटापे का शिकार हो सकता है। मोटापे से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और युवा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है। उन्होंने इस मामले में सतर्क रहने और तेल का सेवन कम करने का आग्रह किया।■

ऋषिकेश में 'कल्याण' के शताब्दी अंक विमोचन समारोह में बोले श्री अमित शाह

गीता प्रेस ने देशवासियों के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा बढ़ाई

सहकार जागरण टीम

- **'कल्याण' ने हर संकट में भारतीय संस्कृति के दीप को जलाए रखने और सनातन धर्म के अनुयायियों की सज्जन शक्ति को संगठित करने का काम किया है**
- **'कल्याण' ने बताया कि सभ्यताएं तलवार से नहीं बल्कि शब्दों और ज्ञान से ही खड़ी होती हैं और शब्द तभी प्रभावी होते हैं जब वे सत्य और सत्व के प्रकाश से चमकते हों**

भारत की संस्कृति को अमर करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रयासों में से सबसे मजबूत प्रयास का नाम 'कल्याण' पत्रिका है। यह एक पत्रिका मात्र नहीं है, बल्कि भारतीयों के लिए आध्यात्मिक जगत का पथप्रदर्शक है। पिछले 100 वर्षों में इसने सनातन धर्म के अनुयायियों की सज्जनशक्ति को संगठित किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को गीता प्रेस के मासिक पत्र 'कल्याण' के शताब्दी अंक के विमोचन के दौरान ऋषिकेश में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कल्याण जैसी पत्रिका का एक शताब्दी पूरा करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक कल्याण का एक-एक शब्द, वाक्य और अंक सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को समर्पित रहा है। यह ज्ञान की सनातन ज्योति को हर वाचक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और इससे देश में सनातन चेतना का उत्सव दिखाई दे रहा है।

श्री शाह ने कहा कि गीता प्रेस का योगदान अतुलनीय है। कल्याण ने हर संकट में भारतीय संस्कृति के दीप को जलाए रखा है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए चलती है। इसने स्वावलंबी तरीके से आदि शंकराचार्य जी के उपनिषदों की मीमांसा और अनेक सद्साहित्य को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। कल्याण ने हमें बताया कि सभ्यताएं तलवार से नहीं, बल्कि शब्दों और ज्ञान से ही खड़ी होती हैं और शब्द तभी प्रभावी होते हैं जब वे सत्य और सत्व के प्रकाश से चमकते हों।

गीता प्रेस का उद्देश्य है चरित्र और राष्ट्र निर्माण

श्री शाह ने कहा कि गीता प्रेस का उद्देश्य चरित्र और राष्ट्र निर्माण है। इसने करोड़ों संतों के अहर्निश प्रयास को रेखांकित कर लोगों

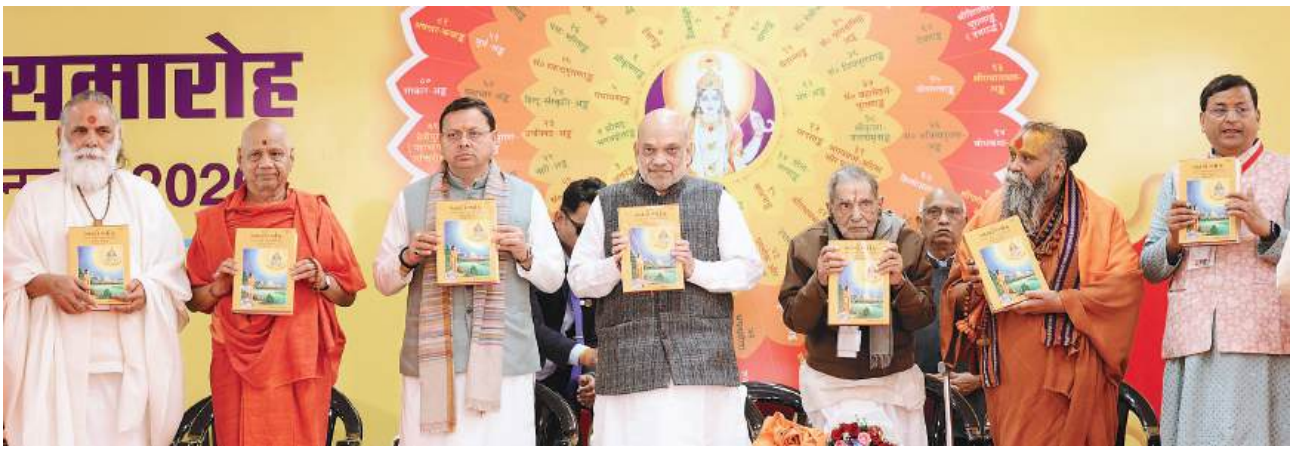

को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया है और अनेक प्रकार के साहित्यों की रचना कर राष्ट्र में एक चेतना की जागृति हुई है। उन्होंने कहा कि करोड़ों संतों ने विकट समय में धर्म, सत्व और संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन किया है और गीता प्रेस और कल्याण जैसी पत्रिकाओं ने सनातन की लौ को हमेशा बचाकर रखा है। इसके कारण हम एक बार फिर से सनातन धर्म के प्रति आकर्षण, आशा और भारतीय संस्कृति में विश्वास दृढ़ होता देख रहे हैं।

श्री शाह ने कहा कि भारत भूमि से प्रेम करने वाला देश और दुनिया का कोई भी व्यक्ति गीता प्रेस से अनजान नहीं हो सकता। कल्याण ने अब तक सनातन समर्पित 100 विशेषांक प्रकाशित किए हैं। उन्होंने कहा कि 1932 के अंक में कल्याण के एक ही अंक में श्री कृष्ण को श्रद्धा की दृष्टि से, राजनीतिज्ञ, तत्वज्ञानी और सभी दुष्टों का दमन करने वाले महापुरुष के रूप में लोगों के सामने रखा। वहीं, 1936 में 'योग अंक' में योग की व्याख्या, स्वरूप और प्रणालियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कल्याण ने सबसे पहले 'नारी अंक' प्रकाशित किया। वहीं, इसका 'हिंदू संस्कृति' अंक 1950 में उस समय आया, जब हमारे देश की नीतियां पाश्चात्य असर से गढ़ी जा रही थीं। इस अंक के पीछे विचार रहा होगा कि जब देश आजाद होकर अपनी नीतियां बना रहा है तब उनके मूल में हमारी भारतीय संस्कृति के विचार समाहित होने चाहिए न कि विदेशी विचार होने चाहिए।

देश के नीति निर्माण में सांस्कृतिक मूल्यों को समाहित कर रही सरकार

श्री शाह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश के नीति निर्माण में सांस्कृतिक मूल्यों को समाहित किया जा रहा है। इस दौरान हमारे युवाओं में एक बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आया है। मातृभाषा में शिक्षा का अब कोई विरोध नहीं हो रहा है। श्री मोदी विश्व में हर जगह जब हिंदी में बोलते हैं तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। श्री शाह ने कहा कि 550 वर्षों बाद रामलला का एक गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में बन चुका है। औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया काशी विश्वनाथ कॉरीडोर पूरी दुनिया को संदेश देता है कि तोड़ने वालों से श्रद्धा की ताकत बहुत बड़ी होती है। श्री शाह ने कहा कि भारत सरकार ने सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक सोमनाथ मंदिर को पूरा वर्ष 'सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ को एक हजार वर्ष पहले गजनी, खिलजी आदि ने 16 बार तोड़ा, जिसे हर बार फिर से बनाया गया। इसे तोड़ने वाले तो कहीं गुम हो गए, लेकिन सोमनाथ की सनातन की ध्वजा आज भी लहरा रही है। कश्मीर से धारा 370 हट गई, महाकालेश्वर का कॉरिडोर बना, केदारनाथ का पुनरुद्धार किया गया, बद्रीधाम का स्ट्रेच पूरा हो चुका है।

गीताप्रेस ने सनातन धर्म की लौ को ताकत दिया

पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने गीता प्रेस के माध्यम से लगभग 103 वर्षों से सनातन धर्म की लौ को ताकत दिया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन गीता प्रेस को समर्पित किया और करोडों लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट श्रद्धा एवं भक्ति के माध्यम से आध्यात्म की ओर प्रेरित किया। इसका उद्देश्य लोगों का मंगल और जगत का कल्याण ही था। श्री शाह ने कहा कि पूरे विश्व के कल्याण की भावना को 'कल्याण' में समाहित किया गया है।

श्री शाह ने कहा कि जब अंग्रेजों का शासन था, तब धर्म को अंधविश्वास कहना एक प्रकार से फैशन बन चुका था। उस वक्त भाई जी ने किसी प्रकार की आक्रामक भाषा का उपयोग किए बिना, कल्याण नाम का ज्ञान का एक दीपक जलाने का काम किया। तर्क, शास्त्र और शांति के माध्यम से जितना विरोध हमारे मूल विचारों का होता था, पोद्दार जी ने उसका उत्तर दिया, क्योंकि सनातन की रक्षा शोर से नहीं, बल्कि शास्त्र और तर्क से ही हो सकती है। श्री शाह ने कहा कि गीता प्रेस ने कभी अपने प्रचार और धन एकत्रित करने के लिए कुछ नही किया, क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्ति-केंद्रित नहीं, बल्कि विचार-केंद्रित था।■

ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाओं का देश है भारत : प्रधानमंत्री श्री मोदी

सहकार जागरण टीम

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। देश में ऊर्जा उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए भी उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। भारत विश्व के शीर्ष पांच पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातकों में से एक है। इसका निर्यात 150 से अधिक देशों तक फैला हुआ है। आज भारत ऊर्जा क्षेत्र में अपार अवसरों का देश है। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 के उद्घाटन समारोह में कही। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ एक समझौता, जिसे दुनिया भर में ‘सर्वोच्च समझौता’ कहा जा रहा है, का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता देश की 140 करोड़ जनता और यूरोपीय देशों के लाखों लोगों के लिए अपार अवसर लेकर आया है। यह समझौता विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय का उल्लेखनीय उदाहरण व वैश्विक जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। व्यापार के अलावा यह समझौता लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।

हर क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी पर भारत के प्रमुखता से काम करने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अकेले ऊर्जा क्षेत्र में ही ऊर्जा मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अपार अवसर मौजूद हैं। भारत ने अपने अन्वेषण क्षेत्र को काफी हद तक खोल दिया है। गहरे समुद्र में अन्वेषण पहल समुद्र मंथन मिशन की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस दशक के अंत तक भारत का लक्ष्य तेल और गैस क्षेत्र में निवेश को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। इसका उद्देश्य अन्वेषण के दायरे को दस लाख वर्ग किलोमीटर तक फैलाना है। इस दिशा में 170 से अधिक ब्लॉक पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं और अंडमान एवं निकोबार बेसिन हाइड्रोकार्बन के अगले स्रोत के रूप में उभर रहा है।

भारत अब ऊर्जा सुरक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा स्वतंत्रता मिशन की ओर बढ़ रहा

अन्वेषण क्षेत्र में कई सुधार करने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऊर्जा सप्ताह के पिछले संस्करणों के दौरान प्राप्त सुझावों को अधिनियमों और नियमों में बदलाव के रूप में शामिल किया गया है। भारत की एक और विशिष्ट शक्ति पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास विशाल शोधन क्षमता है और वर्तमान में इस मामले में वह विश्व में दूसरे स्थान पर है। जल्द ही भारत शोधन क्षमता में विश्व का नंबर एक देश बन जाएगा। भारत की वर्तमान शोधन क्षमता लगभग 260 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और इसे 300 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक करने के लिए प्रयास जारी हैं। देश में एलएनजी की मांग लगातार बढ़ने और अपनी कुल ऊर्जा मांग का 15 प्रतिशत एलएनजी से पूरा करने के लक्ष्य का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने संपूर्ण एलएनजी मूल्य श्रृंखला में मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि भारत परिवहन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहा है। भारत एलएनजी परिवहन के लिए आवश्यक जहाजों का निर्माण कर रहा है। भारतीय बंदरगाहों पर एलएनजी टर्मिनल के निर्माण के साथ-साथ पुनर्गैसीकरण परियोजनाओं में भी निवेश के अनेक अवसर उत्पन्न हुए हैं। शहरी गैस वितरण नेटवर्क पहले ही कई भारतीय शहरों तक पहुंच चुके हैं और अन्य शहरों में तेजी से विस्तार कर रहे हैं। भारत अब ऊर्जा सुरक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा स्वतंत्रता मिशन की ओर अग्रसर है। भारत एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र परितंत्र विकसित कर रहा है जो स्थानीय मांग को पूरा करने में सक्षम है और किफायती शोधन तथा परिवहन समाधानों के माध्यम से निर्यात को विश्व के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बना रहा है।■

पराक्रम दिवस पर बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

आत्मनिर्भरता से अपनी सेनाओं को आधुनिक बना रहा भारत

- पराक्रम दिवस की प्रेरणा भारत के मजबूत संकल्प को करती रहेगी प्रेरित
- भारत शक्ति को हासिल करना, उसे मैनेज करना और उसका इस्तेमाल करना जानता है

सहकार जागरण टीम

एक कमजोर देश अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता, इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा एक मजबूत देश का सपना देखते थे। 21वीं सदी में भारत भी खुद को एक शक्तिशाली और दृढ़ देश के रूप में स्थापित कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने देश को चोट पहुंचाने वालों के घरों में घुसकर उन्हें खत्म करके पलटवार किया। आज भारत जानता है कि शक्ति को कैसे हासिल किया जाता है, उसे कैसे मैनेज किया जाता है और शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नेताजी सुभाष के मजबूत भारत के विजन पर चलते हुए देश रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। पहले भारत सिर्फ.विदेशों से हथियार आयात करने पर निर्भर था, लेकिन आज भारत का रक्षा निर्यात 23 हजार करोड़ से ज्यादा हो गया है। देश में बनी ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइलें दुनिया भर का ध्यान खींच रही हैं। भारत आत्मनिर्भरता की शक्ति से अपनी सेनाओं को आधुनिक बना रहा है। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पराक्रम दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। 1.4 अरब नागरिकों के विकसित भारत के संकल्प की दिशा में काम करने के लिए एकजुट होने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह रास्ता आत्मनिर्भर भारत अभियान से मजबूत हुआ है और स्वदेशी के मंत्र से प्रेरित है। पराक्रम दिवस की प्रेरणा विकसित भारत की इस यात्रा को लगातार ताकत देती रहेगी।

श्री मोदी ने कहा कि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की गौरवशाली तारीख है। नेताजी की वीरता और साहस हमें प्रेरित करते हैं और उनके प्रति हमारे मन में सम्मान भर देते हैं। पराक्रम दिवस देश की भावना का एक जरूरी त्योहार बन गया है। 2026 में पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह अंडमान और निकोबार में आयोजित किए जाने पर श्री मोदी ने कहा कि अंडमान और निकोबार का इतिहास वीरता, बलिदान और साहस से भरा है। सेलुलर जेल में वीर सावरकर जैसे देशभक्तों की कहानियां और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इसका जुड़ाव इस समारोह को और भी खास बनाता है। अंडमान की धरती इस विश्वास का प्रतीक है कि आजादी का विचार कभी खत्म नहीं होता। यहां कई क्रांतिकारियों को यातनाएं दी गईं और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन आजादी की लड़ाई की चिंगारी बुझने के बजाय और मजबूत होती गई। इसके परिणामस्वरूप अंडमान और निकोबार की धरती आजाद भारत की पहली सूर्योदय की गवाह बनी। 1947 से भी पहले 30 दिसंबर 1943 को समुद्र की लहरों की गवाही में यहां तिरंगा फहराया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस न सिर्फ.स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक थे, बल्कि स्वतंत्र भारत के दूरदर्शी भी थे। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी जो आधुनिक होने के साथ-साथ भारत की प्राचीन चेतना से भी जुड़ा हो।■

असम के धेमाजी में 10वां 'मिसिंग यूथ फेस्टिवल'

पूर्वोत्तर भारत के विकास का ग्रोथ इंजन है: श्री अमित शाह

सहकार जागरण टीम

- **देश की रक्षा के लिए मिसिंग समाज ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा**
- **आज असम का युवा हथियारों की जगह विजन और डर की जगह ड्रीम को अपना रहा है**
- **2026 के अंत तक 'मेड इन असम' चिप पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाएगी**

'हमारी सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने असम के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारा मानना है कि भारत में सभी संस्कृतियों, भाषाओं एवं परंपराओं को जीवित रहने का समान अधिकार है और इन सबके संवर्धन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।' केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को असम के धेमाजी में 10वें 'मिसिंग यूथ फेस्टिवल' में व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि मिसिंग समाज हमारे ब्रह्मपुत्र घाटी की धड़कन है। मिसिंग संस्कृति असम और भारत की संस्कृति की आत्मा, जीवंत पहचान और आने वाले भारत का एक प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों, संस्कृति, भाषा, साहित्य, नृत्य और संगीत की रक्षा करने का रास्ता हाथ में बंदूक लेकर नहीं, बल्कि 'यूथ फेस्टिवल' के माध्यम से ही हो सकता है। यह दृष्टिकोण असम को आगे ले जा रहा है, जहां सरकार ने 200 लोअर प्राइमरी स्कूलों में मिसिंग भाषा को शिक्षा के माध्यम से रूप में स्वीकार किया है। श्री शाह ने कहा कि असम सरकार ने एक लाख 26 हजार एकड़ भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराया है।

श्री शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने जहां 10 वर्षों में असम के लिए एक लाख 28 हजार करोड़ रुपए दिए थे, वहीं श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने असम के विकास के लिए चार लाख 50 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। हमारी सरकार ने असम में सड़क निर्माण के लिए 30 हजार करोड़ रुपए, रेलवे के लिए 95 हजार करोड़ और एयरपोर्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए दिया है। श्री शाह ने कहा कि कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने जनजाति आयोग और जनजाति मंत्रालय का गठन किया और मोदी सरकार ने 15 नवंबर को आदिवासी गौरव

दिवस घोषित किया है और देशभर में 200 करोड़ के बजट से आदिवासी म्यूज़ियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक की पिछली सरकार में जनजाति कल्याण मंत्रालय और एसटी कंपोनेंट का कुल बजट 28 हजार करोड़ रुपए ही था, जबकि मोदी सरकार ने पिछले बजट में एक लाख 35 हजार करोड़ रुपए का आदिवासी विकास के लिए प्रदान किया। हमारी सरकार ने एकलव्य रेज़िडेंशियल स्कूल का बजट भी 25 गुना बढ़ाया है।

शांति और विकास की मुख्यधारा में लौटे 10 हजार युवा

श्री शाह मे कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में असम शांति के रास्ते पर चल रहा है। सरकार ने कई समझौते कर लगभग 10 हजार युवाओं के हाथ से हथियार छुड़ाए हैं। इससे असम का युवा अब हथियारों की जगह आगे बढ़ने के 'विजन' और डर की जगह प्रगति के सपने को अपना रहा है। यहां हमने बिना सिफारिश के लगभग एक लाख 56 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। यहां लगने वाली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री से 27 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी मिलेगी और 2026 के अंत तक असम में बनी चिप पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। श्री शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में केंद्रीय सशस्त्र बलों में मिसिंग युवाओं की विशेष भर्ती भी होगी, जिससे स्थानीय युवा भारत की आंतरिक सुरक्षा में अपना सक्रिय योगदान दे सकेंगे।

पूरे असम को घुसपैठिया-मुक्त बनाना हमारी जिम्मेदारी

श्री शाह ने कहा कि मिसिंग समाज की ज़िम्मेदारी पूरे असम को घुसपैठिया-मुक्त करने की है। उन्होंने कहा कि हमारे सात ज़िले, जो आज घुसपैठिया-बहुल हो गए हैं और पूर्ववर्ती सरकारों के 20 वर्षों के शासन में इन ज़िलों में घुसपैठियों की आबादी लाखों में हो गई है। इससे राज्य की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई है, जिसे 'रिवर्स' करने का काम हमारी सरकार करेगी। श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस घुसपैठ को रोकने और घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकालने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'हाई-पावर डेमोग्रैफी चेंजिंग मिशन' की घोषणा की थी। यह मिशन देशभर में अप्राकृतिक तरीके से हो रहे डेमोग्राफिक परिवर्तन का अभ्यास कर इसका उपाय सुझाएगा। ■

स्वतंत्रता संग्राम में मिसिंग समाज का अमूल्य योगदान

श्री शाह ने कहा कि हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मिसिंग समाज के योगदान को भूल सकते, जब हर संघर्ष में मिसिंग समाज ने भारत की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस समाज ने नदियों को रास्ता देकर बाढ़ को कम करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि एक जमाने में अलग अलग जनजातियां अपनी संस्कृतियों की रक्षा के लिए संघर्ष करती थीं और तत्कालीन सरकारें इन सभी को कुचल कर रखना चाहती थीं। लेकिन, हमारी सरकार ने वातार्कार नियुक्त किया है जो सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेंगे। श्री शाह ने कहा कि बोगीबील ब्रिज की रचना हमारे मिसिंग श्रमिक भाईयों-बहनों के पसीने से हुई है। यह ब्रिज आज पूरे विश्व में नए भारत की कल्पना का प्रतीक बना है जिसे मोदी सरकार ने केवल चार वर्षों में ही पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अली-आये-लिगांग प्रकृति के साथ संतुलन मिलाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री शाह ने कहा कि प्रकृति पूजा, पूर्वज पूजा, और सत्य एवं नैतिकता को सर्वोच्च मानने वाले 'डोनी-पोलो' धर्म सिर्फ असम और अरुणाचल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत को दुनियाभर में प्रसिद्ध बनाती है।

पश्चिम बंगाल के मालदा में रेल-सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ

आधुनिक व आत्मनिर्भर हो रही भारतीय रेलवे : प्रधानमंत्री श्री मोदी

सहकार जागरण टीम

▸▸ भारत में शुरू की जा रही हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें

▸▸ आगामी समय में पूरे देश में आधुनिक ट्रेनों का होगा विस्तार

भारतीय रेलवे न केवल आधुनिक बन रही है बल्कि आत्मनिर्भर भी हो रही है। भारत के रेल इंजन, कोच और मेट्रो कोच भारत की प्रौद्योगिकी के प्रतीक के रूप में उभर रहे हैं। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में 3,250 करोड़ रुपए की लागत वाली कई रेल और सड़क बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन और नींव रखते हुए कही। भारत द्वारा अमेरिका और यूरोप से अधिक लोकोमोटिव का निर्माण करने और कई देशों को यात्री ट्रेन और मेट्रो ट्रेन कोच निर्यात करने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होता है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। भारत को जोड़ना उनकी प्राथमिकता है और दूरियों को कम करना एक मिशन।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मालदा से पश्चिम बंगाल की प्रगति को गति देने के अभियान को और गति मिली है। पश्चिम बंगाल के लिए नई रेल सेवाएं शुरू की गई हैं। इनसे लोगों की यात्रा आसान होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यहां स्थापित नई रेल रखरखाव सुविधाएं बंगाल के युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करेंगी।

बंगाल की पवित्र भूमि से भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाए जाने की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने बताया कि भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। यह नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नागरिकों की लंबी यात्राओं को अधिक आरामदायक और शानदार बनाएगी। विकसित भारत में ट्रेनों का स्वरूप इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में स्पष्ट रूप से झलकता है। पहले लोग विदेशी ट्रेनों की तस्वीरें देखकर भारत में ऐसी ट्रेनों की कामना करते थे और आज उनका यह सपना साकार हो रहा है। विदेशी पर्यटक भारतीय रेलवे में हो रहे क्रांतिकारी बदलावों के वीडियो बना रहे हैं। यह वंदे भारत ट्रेन 'मेड इन इंडिया' है जो भारतीयों की मेहनत और समर्पण से बनी है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की भूमि को मां कामाख्या की भूमि से जोड़ रही है। आने वाले समय में इस आधुनिक ट्रेन का पूरे देश में विस्तार होगा।

भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण और स्टेशनों के आधुनिकीकरण के साथ परिवर्तन के दौर से गुजरने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने बताया कि पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। इसके साथ ही आधुनिक और उच्च गति वाली ट्रेनों का एक संपूर्ण नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को काफी लाभ मिल रहा है।■

पश्चिम बंगाल के सिंगूर में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण

विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास प्राथमिकता : प्रधानमंत्री

सहकार जागरण टीम

पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की गई। बंगाल को लगभग आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली हैं। तीन और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की गई हैं। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए यह विचार व्यक्त किया। बंगाल में जलमार्गों की अपार संभावनाएं होने और इस दिशा में कार्य जारी होने की बात कहते हुए श्री मोदी ने बताया कि बंदरगाह आधारित विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। कुछ समय पहले ही बंदरगाहों और नदी-जलमार्गों से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये पश्चिम बंगाल और भारत के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये वे स्तंभ हैं जिन पर पश्चिम बंगाल को विनिर्माण, व्यापार और रसद के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।

बंदरगाहों और उनसे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र पर फोकस करने से अधिक मात्रा में रोजगार सृजित होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की क्षमता विस्तार में महत्वपूर्ण निवेश किया है। सागरमाला योजना के तहत इस बंदरगाह की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सड़कों

बालागढ़ में बन रही विस्तारित बंदरगाह द्वार प्रणाली हुगली ओर आसपास के क्षेत्रों के लिए नए अवसर खोलेगी

का निर्माण भी किया गया है। इन प्रयासों के परिणाम अब दिखने लगे हैं। पिछले वर्ष कोलकाता बंदरगाह ने माल ढुलाई में नए रिकॉर्ड बनाए। बालागढ़ में विकसित की जा रही विस्तारित बंदरगाह द्वार प्रणाली हुगली और आसपास के क्षेत्रों के लिए नए अवसर खोलेगी। इससे कोलकाता शहर में यातायात और रसद का दबाव कम होगा। गंगा पर बने इस जलमार्ग के माध्यम से माल ढुलाई में और वृद्धि होगी। यह संपूर्ण अवसंरचना हुगली को एक भंडारण और व्यापार केंद्र में बदलने में सहायक होगी। इससे सैकड़ों करोड़ का नया निवेश आएगा, हजारों रोजगार सृजित होंगे, छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को लाभ होगा और किसानों और उत्पादकों के लिए नए बाजार उपलब्ध होंगे।

श्री मोदी ने कहा कि भारत आज बहु-मार्गीय संपर्क और हरित परिवहन पर विशेष बल दे रहा है। सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के लिए बंदरगाहों, नदी-मार्गों, राजमार्गों और हवाई अड्डों को आपस में जोड़ा जा रहा है। इससे रसद लागत और परिवहन समय दोनों में कमी आ रही है। परिवहन के साधनों को प्रकृति के अनुकूल बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नौकाएं नदी परिवहन और हरित परिवहन को मजबूत करेंगी। इससे हुगली नदी पर यात्रा आसान होगी, प्रदूषण कम होगा और नदी आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य उत्पादन एवं निर्यात में भारत की तेज प्रगति का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने का सपना व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नदी-जलमार्गों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण का प्रमुखता से समर्थन कर रही है। इससे किसानों और मछुआरों दोनों को लाभ मिल रहा है। ■

आणंद में चारुसत के 15वें दीक्षांत समारोह में बोले श्री अमित शाह

बीते 11 वर्षों में सतत विकास की परंपरा हुई स्थापित

सहकार जागरण टीम

- **वर्ष 2047 तक विश्व में हर क्षेत्र में देश को सर्वप्रथम बनाने के लिए किया जा रहा पुरुषार्थ, परिश्रम और प्लानिंग**
- **15 अगस्त 2047 को जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब भारत विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में अनेक प्रकार के विकास की शुरूआत के जरिए सतत विकास की परंपरा स्थापित हुई है। इसके कारण पूरे विश्व में देश का सम्मान बढ़ा है और युवाओं के लिए विपुल संभावनाएं खुली हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को गुजरात के आणंद जिले में चरोतर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (चारुसत) के 15वें दीक्षांत समारोह के दौरान साझा किया। श्री शाह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री ने देश के सामने संकल्प रखा कि 15 अगस्त 2047 को जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब भारत विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा। यह संकल्प देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन गया है और इस दिशा में पुरुषार्थ, परिश्रम और प्लानिंग की जा रही है।

श्री शाह ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों में हमने काफी कुछ प्राप्त किया और अनेक क्षेत्रों में प्रगति की, परंतु 75 वर्ष से 100 वर्ष का यह कालखंड देश के लिए अमृतकाल और संकल्पकाल है। हमने देश में अबतक अनेक लक्ष्य हासिल किए है। अब से 11 वर्षों पहले वर्ष 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, जो अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका अर्थ है देश के युवाओं के लिए विकास के लिए अपार संभावनाएं। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि 31 दिसम्बर 2027 के दिन हम विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। इसप्रकार, देश में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां से भारत के युवा विश्व भर के युवाओं से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

श्री शाह ने कहा कि भारत अब पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित है जो आगामी 25 वर्षों की विश्व की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने की क्षमता रखता है। ग्रीन एनर्जी और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज समग्र विश्व भारत की अनदेखा नहीं कर सकता। ग्रीन हाइड्रोजन में हमारी मजबूत

शुरूआत हुई है। रक्षा उत्पादों में हमने दिन-दुगुनी रात-चौगुनी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में भारत के विकास को देखकर आज पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। वहीं, फार्मास्यूटिकल्स में विश्व की साठ प्रतिशत दवाइयां भी हमारे देश में बनती हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश में मूलभूत परिवर्तन

श्री शाह ने कहा कि दूरदर्शी प्लानिंग के साथ बीते ग्यारह वर्षों में देश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। इससे शैक्षिक संस्थानों में सीटों की संख्या, कोर्स डिजाइन और शिक्षा के बाद मिलने वाले अवसरों की संख्या में वृद्धि जैसे बुनियादी सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या आजादी से 2014 तक 51 हजार थी, जो पिछले वर्षों में 20 हजार बढ़कर 71 हजार पहुंच गई है। इस दौरान देश में कॉलेज की संख्या 38 हजार 498 से बढ़कर अब 53 हजार हो गए हैं और विश्वविद्यालय भी 760 से बढ़कर 1391 हो गए हैं। श्री शाह ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 818 हो जाने के साथ ही एमबीबीएस सीटों की संख्या 51 हजार से बढ़कर एक लाख 29 हजार हो गई है और पीजी सीटों की संख्या 31 हजार से 82 हजार हुई है। इसप्रकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए विकास के अपार अवसर सृजित हुए हैं। श्री शाह ने कहा कि स्टार्टअप कल्चर भारत के युवाओं का स्वभाव है। हम विश्व में स्टार्टअप की संख्या में और यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या में तीसरे नंबर पर हैं।

ज्ञान व अच्छे चरित्र से समाज के नवनिर्माण में योगदान करें युवा

चरोतर यूनिवर्सिटी के छात्रों को अपने ज्ञान व अच्छे चरित्र से समाज के नवनिर्माण में योगदान करने का आह्वान करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल का यह कथन कि 'चरित्र निर्माण के बिना शिक्षा बेकार है', हम सभी के जीवन का मूल वाक्य है। शिक्षा मात्र डिग्री या स्किल बढ़ाने तक सीमित नहीं होती। युवाओं और विद्यार्थियों को अनुशासन एवं उनका चरित्र का निर्माण करने के लिए और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का परिचय कराने का काम शिक्षा का है। उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा मानव, समाज या देश का कल्याण नहीं कर सकती। ज्ञान और चरित्र दोनों एक साथ होने पर ही मानव और समाज दोनों के लिए उपयोगी बनता है। ज्ञान से सक्षमता आती है और जिस जीवन का उद्देश्य नहीं होता, वह जीवन कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता।

श्री शाह ने युवाओं को जीवन की दिशा देने वाली सीख देते छह सूत्र प्रदान किए, जिनमें देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा, प्रोत्साहन और आत्मविकास के साथ ही राष्ट्र विकास की व्यापक भावना समाहित हैं-

- जीवन में हमेशा बड़े सपने देखें, असफलता का डर निकाल दें और पुरुषार्थ करने की हिम्मत रखें, देखे गए सपने जरूर पूरे होंगे।
- टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त युवा इस बात पर सतत विचार करें कि टेक्नोलॉजी का उपयोग समाज और देश के लिए किस प्रकार किया जा सकता है।
- निरंतर सीखते रहें और अपने भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने न दें।
- सीखने के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है।
- टेक्नॉलजी के ज्ञान के मामले में कभी शॉर्टकट नहीं अपनाने का संकल्प लें, और
- देश से ऊपर कुछ नहीं है। अपना काम देश को 2047 में महान बनाने की कल्पना के साथ करें।

श्री शाह ने कहा कि जीवन में उन्हीं लोगों ने कुछ प्राप्त किया है, जिन्होंने उद्देश्य निश्चित करके उसकी पूर्ति के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि चारुसत से ग्रेजुएट, डॉक्टरेट या डबल ग्रेजुएट होकर निकलने वाले हर विद्यार्थी का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह 2047 में महान भारत की रचना के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। ■

सहकारिता का विचार आज देश की जरूरत

श्री शाह ने कहा कि चरोतर की भूमि ने भारत को बहुत कुछ दिया है। इस भूमि पर जन्मे सरदार वल्लभभाई पटेल, विठ्ठलभाई पटेल और हिरुभाई एम. पटेल जैसे रत्नों ने भारत को हर क्षेत्र में कुछ न कुछ दिया है। अमूल, जिसकी सफलता से पूरा विश्व आश्चर्यचकित है, का मूल विचार भी चरोतर की इसी भूमि ने दिया। अमूल आज को-ऑपरेटिव सेक्टर में विश्व की नंबर वन को-ऑपरेटिव संस्था है जिसका टर्नओवर आज एक लाख करोड़ रुपए का है और गुजरात की बीस लाख से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ी हैं। आणंद में हाल ही में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का जिक्र करते हुए कहा कि अमूल की स्थापना भी त्रिभुवनदास जी ने की और इस देश में सहकारिता का एक ऐसा विचार प्रस्थापित किया और उसे सफल बनाया, जो आज भी इस देश की जरूरत है।

'परीक्षा पे चर्चा' के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बोले

शिक्षा व्यक्तिगत विकास के साथ सामाजिक जीवन के लिए भी जरूरी

सहकार जागरण टीम

- तुलना के दबाव में आने के बजाय, सीखने और बेहतर करने का करें प्रयास
- पढ़ाई में संघर्ष करने वालों से दोस्ती करें और उन्हें सीखने में मदद करें

शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि सामाजिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। इसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए। खेलों को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को दिन में कम से कम एक बार श्वास संबंधी व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' के दौरान कही। पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना हमारी आदत बन जानी चाहिए। बदलाव धीरे-धीरे ही आता है, जब अधिक से अधिक लोग एक साथ आते हैं। नेतृत्व पर एक प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा कि भावी नेताओं को अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में सक्षम होना चाहिए। सीखने में केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि लिखना और अभ्यास करना भी शामिल होना चाहिए।

विद्यार्थियों से केवल सफलता से प्रभावित न होने और महान व्यक्तित्वों की साधारण शुरुआत से सीखने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ने अभिभावकों को घर में प्रतिस्पर्धा का माहौल न बनाने की सलाह दी और विद्यार्थियों से कहा कि वे अनुचित तुलना से बचें और आत्म-सुधार पर ध्यान केंद्रित करें।

परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने विद्यार्थियों को परीक्षाओं से परे देखने और जीवन कौशल, खेल, रचनात्मकता तथा आत्म-विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा। विद्यार्थियों को छोटे स्टार्टअप से अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े विचार अक्सर छोटी शुरुआत से ही पनपते हैं। विद्यार्थियों को उद्योग जगत के पेशेवरों से संपर्क बनाने, वास्तविक दुनिया की प्रणालियों की कार्यप्रणाली को समझने और पाठ्यपुस्तकों से परे व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की सलाह दी।

पढ़ाई और रुचि के बीच संतुलन बनाए रखने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अकादमिक और रचनात्मक गतिविधियों को अलग या विरोधी रास्ता नहीं समझना चाहिए। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और प्रभावी ढंग से संतुलित किए जा सकते हैं। कलात्मक तथा रचनात्मक शौक विद्यार्थियों को अकादमिक दबाव से उत्पन्न तनाव और थकान से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि अनुशासित

दैनिक व्यवहार राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

'वोकल फॉर लोकल' जैसी पहलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उत्पादों का चयन घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। विदेश के बजाय देश में ही शादी करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले 'वेड इन इंडिया' अभियान का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों द्वारा उठाया गया हर छोटा कदम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देता है। अनुशासन और प्रेरणा दोनों को आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि अनुशासन के बिना केवल प्रेरणा अक्सर अप्रभावी होती है। अनुशासन दिशा देता है जबकि प्रेरणा यात्रा को मजबूत बनाती है।

कृत्रिम मेधा और प्रौद्योगिकी से डरने की सलाह देते हुए श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को इस पर निर्भर होने के बजाय इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली शिक्षक है। जागरूकता तथा जिम्मेदारी के साथ इसे अपनाना चाहिए, वे इसे सीखने, नवाचार और विकास के साधन के रूप में उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे केवल पर्यटक बनकर नहीं, बल्कि शिक्षार्थी बनकर यात्रा करें। विद्यार्थियों को जिज्ञासा, संस्कृति, इतिहास और जीवनशैली को समझने की इच्छा के साथ नए स्थानों का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक अच्छा विद्यार्थी विषयों पर मजबूत पकड़ बनाता है, निरंतर प्रयास करता है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के साथ ही उन सहपाठियों से दोस्ती करता है, जो शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें सीखने में मदद करता है।

एक छात्र के स्टार्टअप से संबंधित जिज्ञासा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने सलाह दी कि सबसे पहले अपनी रुचि और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वह प्रौद्योगिकी में नवाचार हो, ड्रोन का विकास हो या विद्युत प्रणालियों जैसे व्यावहारिक समाधान। तकनीक और वित्त में कुशल मित्रों के साथ छोटी टीमें बनाना सहायक हो सकता है। उद्यम शुरू करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती और छोटे स्टार्टअप भी प्रभावशाली हो सकते हैं। उन्होंने मौजूदा स्टार्टअप्स का दौरा करने, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने और उसे ईमानदारी से एक स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिससे मार्गदर्शन और समर्थन को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रक्रिया के दौरान धीरे-धीरे आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, जो आगे के प्रयासों में सहायक होगा। पढ़ाई और शौक के बीच संतुलन बनाने की एक छात्र की चिंता को दूर करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों ही उपयोगी हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। कला और विज्ञान के प्रयोगों को मिलाकर एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि रचनात्मकता सीखने में मदद कर सकती है और थकान कम कर सकती है। शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपनी व्यक्तिगत रुचियों के लिए भी प्रतिदिन या साप्ताहिक समय निकालना जरूरी है।

करियर विकल्पों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार बदलती आकांक्षाएं भ्रमित कर देती हैं। हमें सफल लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए और न केवल उनकी उपलब्धियों को देखना चाहिए, बल्कि उनके पीछे के प्रयास और अनुशासन को भी समझना चाहिए। सच्ची सफलता खुद अपनी पहचान बनाती है। सफल विद्यार्थी को पूरा स्कूल, गांव और समुदाय पहचान लेता है। भय और आत्मविश्वास के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं, वे कभी नहीं डरते और वे कार्य करने से पहले स्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हैं। स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध शिकागो भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि विवेकानंद शुरू में घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने शक्ति के लिए मां सरस्वती से प्रार्थना की और जब ₹अमेरिका के बहनों और भाइयों₹ से शुरुआत की, तो श्रोताओं ने कई मिनटों तक तालियां बजाईं, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।■

भारत होगा सशक्त, बनेगा आत्मनिर्भर : श्री गुर्जर

केंद्रीय बजट 2026-27 में युवाओं को अवसर, महिलाओं को सशक्त मंच, किसानों को स्थिरता और उद्यमियों को विस्तार का भरोसा

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश की आर्थिक प्रगति में सामाजिक समावेशन पर विशेष जोर दे रही है। वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में भी इस दिशा में ठोस पहल किए गए है, जिसमें युवाओं को अवसर, महिलाओं को सशक्त मंच, किसानों को स्थिरता और उद्यमियों को विस्तार का भरोसा मिला है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने इन तथ्यों को सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त किया और कहा कि यह बजट भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। श्री गुर्जर ने इसे 'समृद्ध किसान, सशक्त भारत' की संकल्पना से प्रेरित बताते हुए कहा कि इसमें किसानों को हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। खेती का नया रोडमैप देने वाला यह बजट न केवल किसानों की आय बढ़ाने वाला है, बल्कि खेती को आधुनिक तकनीक व टिकाऊ संसाधनों से जोड़ने वाला भी है। फसलों के उत्पादन से लेकर उसके विपणन तक में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। किसानों को उचित कीमत पर बीज, खाद, कीटनाशक और आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। 500 जलाशयों व अमृत सरोवरों के विकास के साथ ही देश के भीतर मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। नारियल किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादकता में वृद्धि के लिए नारियल संवर्धन होगा।

बजट में औद्योगिक क्षमता के विस्तार और क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए नए अवसर का प्रावधान है। इसके लिए देश भर में स्किल लैब्स की स्थापना की जाएगी और इस क्षेत्र में 2030 तक 20 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। तीन समर्पित केमिकल पार्क की स्थापना के साथ ही निर्माण व इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों के लिए नई योजना भी है। देश में कंटेनरों के निर्माण को बढ़ावा देने को 10 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट में 200 औद्योगिक क्लस्टर्स के पुनरुद्धार और सात हाई-स्पीड कॉरिडोर के जरिए देश को नई कनेक्टिविटी देने की घोषणा भी की गई है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सशक्त करने के लिए दस हजार करोड़ का फंड बनाया गया है। इसके साथ ही दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने और आयात कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत फंड में दो हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जोड़ी गई है। टियर-II व टियर-III शहरों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 'कॉरपोरेट मित्र' का सहयोग लिया जाएगा। ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उनके बनाए उत्पादों के लिए एसएचई माट्र्स के जरिए बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। गांवों में कार्य कर रही महिला उद्यमियों को नवाचार व उनके नेतृत्व में चल रही औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाले इस बजट में देश को बायोफार्मा हब बनाने का जिक्र करते हुए श्री गुर्जर ने कहा कि आयुर्वेद आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। बजट में घोषित तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और 10 हजार करोड़ का फंड इस क्षेत्र में भारत को दुनिया का अगुवा बनाने में योगदान देंगे। अब कैंसर, डायबिटिज और प्रतिरोधक क्षमता बढाने वाली दवाएं सस्ती होंगी और इनकी आयात निर्भरता भी कम होगी। स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के लिए अगले पांच वर्षों में एक लाख सहायक मेडिकल पेशेवर तैयार किए जाएंगे और जिला अस्पतालों की क्षमता में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। राज्यों को पांच मेडिकल हब स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता प्रदान करेगी। अब देश अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होगा। इसके लिए कृषि से लेकर विनिर्माण क्षेत्र में सक्रिय उद्योगों को हर तकनीकी व आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। आधुनिक तकनीक के विकास के लिए देश में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे विदेशी निर्भरता धीरे-धीरे खत्म की जाएगी। श्री गुर्जर ने कहा कि यह बजट देशवासियों के उस सपने को शक्ति देता है, जिससे हम एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत को साकार कर रहे हैं।■

बड़गांव कृषि सेवा सहकारी समिति ने बदली किसानों की तकदीर

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा और गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' का विचार लगातार जमीन पर साकार होता जा रहा है। इस विचार से प्रेरित सहकारी समितियां अपने सदस्यों व अन्य को सशक्त बना रही हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित बड़गांव कृषि सेवा सहकारी समिति 62 वर्षों से किसानों की तरक्की की मजबूत साथी बनी हुई है। बदलते समय के साथ कदमताल करते हुए समिति ने आधुनिक तकनीक व बेहतर संसाधनों के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा दी है। समिति के प्रयासों से आई आर्थिक स्थिरता, रोजमर्रा की जरूरतों की आसान उपलब्धता और नए बाजारों से जुड़ने के मौके ने गांव की तस्वीर व किसानों की तकदीर बदल दी है।

वर्ष 1952 सदस्यों वाली यह समिति विभिन्न सेवाओं के जरिए अपने सदस्यों के सशक्तीकरण में लगी है। समिति जमा सुविधा उपलब्ध कराती है। इसका लाभ उठाते हुए समिति के सदस्य इसके पास धन जमा कराते हैं। इस जमा धन पर समिति सदस्यों को ब्याज उपलब्ध कराती है और उस पैसे का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल करती है। समिति सदस्यों को ऋण की भी सुविधा देती है। इस सुविधा का लाभ उठाते हुए किसान अपनी जरूरतों के लिए समिति से ऋण लेते रहते हैं और समय पर उसका भुगतान भी कर देते हैं। समिति के पास किसान क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा है।

सहकारी समिति सदस्य किसानों बीमा की सेवाएं भी देती है। सदस्य जीवन और सामान्य बीमा कराते हैं। उन्हें बहुत कम प्रीमियम पर यह सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए पूरी पारदर्शिता का पालन किया जाता है। इससे किसानों का विश्वास बढ़ता है और वे बढ़चढ़कर आगे आते हैं। कामन सर्विस सेंटर के जरिए समिति अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के लिए अब सदस्यों को भटकना नहीं पड़ता। समिति के जरिए अब वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाते हैं। घर बैठे उन्हें जरूरी दस्तावेज और अन्य कागजात उपलब्ध हो जाते हैं। समिति के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आउटलेट भी है। इसके जरिए किसानों को अब सस्ता राशन पास में ही मिल जाता है। उसमें अब किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत नहीं आती। समिति इलेक्ट्रानिक स्टोर का संचालन भी करती है। इसके सदस्यों व अन्य लोगों को इलेक्ट्रानिक के सामान समिति के स्टोर पर उचित दाम पर मिल जाते हैं।

किसानों को अब उच्च गुणवत्ता के बीज, पौधे, उर्वरक, कीटनाशी व खरपतवारनाशी, स्प्रे पंप और खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। ये सब चीजें समिति उपलब्ध कराती है। किसान इसका लाभ उठाते हैं। इससे उन्हें उचित कीमत पर गुणवत्तायुक्त संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। इसके जरिए वे फसलों का अधिकतम उत्पादन कर पाते हैं। इससे उनका आर्थिक सशक्तीकरण होता है। उनके परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में समिति को 9 लाख 72 हजार 253 रुपए का लाभ हुआ। समिति ने अपने सदस्यों को 1 लाख 5 हजार 472 रुपए का लाभांश प्रदान किया। समिति ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए बड़गांव फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन की शुरुआत भी की है। भविष्य में समिति का लक्ष्य किसानों की आय में वृद्धि और स्थानीय उत्पादों के लिए नया बाजार उपलब्ध कराने की है। वित्तीय सेवाओं, किसानों को ऋण प्रदान करने और ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए समिति की उपलब्धियों व उसके कार्यों को देखते हुए प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी अवार्ड से सम्मानित किया गया।■

डॉ. के. के. त्रिपाठी

आम बजट में सहकारिता के विकास पर जोर

संसद में पेश वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सहकारी समितियों को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक कदम है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसमें व्यवहारिक रास्ता बताया गया है। विकास-केंद्रित बजट में बुनियादी ढांचे के विकास और सुधारों पर जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य देश के विकास की यात्रा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहभागी बनाना है। इसमें उद्यमिता, मूल्यवर्धन और संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। बजट में सहकारी समितियों के संचालन को पेशेवर बनाने, बाजारों का विस्तार करने और किसानों की आय बढ़ाने का भी प्रावधान है।

प्राथमिक सहकारी समितियां (पैक्स) लंबे समय से करों में राहत का इंतजार कर रहीं थीं। बजट में उनका इंतजार खत्म हो गया है। इसमें समितियों के सदस्य किसानों द्वारा पैदा किए गए तिलहन, फल और सब्जियों की आपूर्ति करने वाली सहकारी समितियों को कर कटौती के दायरे में लाया गया है। इससे बाजार में उनकी स्थिति मजबूत होगी। यह कदम संघीय सहकारी समितियों के साथ उनके तालमेल को बढ़ावा देता है। इससे प्राथमिक इकाइयों को अपना विस्तार करने, एकीकृत होने और बाजार के होड़ में बने रहने में मदद मिलती है। करों में राहत मिलने से सहकारी समितियों की आय बढ़ेगी। बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और गुणवत्तापूर्ण इनपुट में निवेश बढ़ेगा। सरकार का यह कदम प्राथमिक सहकारी समितियों को संघीय सहकारी समितियों को आवश्यक कृषि-इनपुट की आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे समितियों के सदस्य किसानों को सस्ते दर पर खेती के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते है। लागत में कमी आने से जहां खेती करना आसान होता है, वहीं कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इससे सहकारी समितियों की प्रतिस्पर्धा की क्षमता में वृद्धि होती है। यह बजट नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगर लाभांश समितियों के सदस्यों को दिया जाता है, तो इंटर-कोऑपरेटिव सोसाइटी डिविडेंड इनकम पर करों में कटौती की अनुमति देता है। यह कोऑपरेटिव चेन के भीतर दोहरी कर प्रणाली को खत्म करता है और यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स केवल सदस्य स्तर पर ही लगाया जाए। इस कदम से प्राथमिक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के बीच संबंध और मजबूत होता है।

बजट में सहकारिता के क्षेत्र में निवेश और आय सृजन को बढ़ावा दिया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि इससे होने वाला लाभ सहकारी समितियों को वापस मिले। यह कदम सहकारिता के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देता है। इस पहल से सहकारी समितियां अधिक पेशेवर और प्रतिस्पर्धी बनेंगी। इससे सरकारी अनुदान या सब्सिडी पर उनकी निर्भरता कम होगी।

बजट में कृष उत्पादन और उनके कारोबार में वृद्धि के जरिए ग्रामीण आय बढ़ाने का प्रयास किया गया है। सहकारी समितियां किसानों से कृषि उत्पादों को इकट्ठा कर और उसे बाजार तक पहुंचाकर उनकी आय में वृद्धि कर सकती हैं। इससे विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचेगा। सहकारी समितियां अपनी पेशेवर कार्यप्रणाली से अपने सदस्य किसानों की स्थाई आय-सृजन में एक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो सकती हैं। बजट में पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। जलाशयों के विकास, उसमें मत्स्य पालन और पशुधन के विकास के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें सहकारी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उपरोक्त संसाधनों का इस्तेमाल कर सहकारी समितियां विकास को तेज गति प्रदान कर सकती हैं। समितियां उत्पादन बढ़ाने के साथ प्रसंस्करण और ब्रांडिंग के माध्यम से उत्पादों का मूल्य भी बढ़ा सकती हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है।

बजट में पेश महात्मा गांधी स्वराज पहल से हथकरघा सहकारी समितियों को सशक्त बनाया गया है। इससे इस क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों को लाभ होगा। आर्थिक व तकनीकी रूप से सशक्त समितियां हथकरघा उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाकर और अपने सदस्यों का कौशल विकास व आधुनिकीकरण कर उनकी आय बढ़ा सकती हैं। इसके लिए समितियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता होनी चाहिए और उन्नत तकनीक के साथ पेशेवर रणनीति भी जरूरी है। बजट में सहकारिता मंत्रालय को आवंटित 1,744.7 करोड़ रुपए में से 450 करोड़ रुपए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) को दिया गया है। इसके जरिए यह संगठन मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और उच्च मापदंडों के लिए आर्थिक मदद कर सहकारी निर्यात को बढ़ावा देगा। इससे दुनिया के बाजारों में कृषि उत्पादों मांग और उसकी आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बजट में प्राथमिक सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 364 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह आवंटन ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे समितियों में पारदर्शिता आएगी, तेजी से कार्य हो सकेगा और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। समय की जरूरत है कि सहकारी ट्रेनिंग और शिक्षा के लिए बजट में आवंटित 357 करोड़ रुपए को ठोस नतीजों में बदला जाए। सहकारी समितियों को पेशेवर बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।■

संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) ने नई दिल्ली में यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम का सफल आयोजन किया, जिसमें 53 युवाओं को सहकारिता का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कराते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन और बाय-लॉज का ड्राफ्ट बनाने जैसे विषयों की जानकारी दी गई। एनसीयूआई की डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव श्रीमती सावित्री सिंह ने प्रतिभागियों से बातचीत की।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के भगिनी निवेदिता कॉलेज में एनसीयूआई ने सहकारिता पर एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एनसीयूआई की डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव श्रीमती सावित्री सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रितेश डे और राजीव शर्मा ने छात्रों को सहकारी विकास में युवाओं की भूमिका और कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी दी।

एनसीयूआई के नेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन (एनसीसीई) ने सहकारिता के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग, शिक्षा और क्षमता निर्माण के ट्रेनिंग प्रोग्राम के तौर पर पश्चिम बंगाल के प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए नई दिल्ली के कृभको का एक शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया, जहां उन्हें मिट्टी और बीज परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण और नवाचार का व्यावहारिक अनुभव मिला।

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) ने मिजोरम में सहकारिताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें सियाहा, लॉन्गटलाई और लुंगलेई जिलों की सहकारी समितियों के अध्यक्षों, बोर्ड सदस्यों और उत्साही युवाशक्ति की बड़ी भागीदारी से जमीनी स्तर पर सहकारिता की भावना मजबूत हुई।

एनसीयूआई ने मिजोरम सरकार के सहकारिता विभाग के साथ मिलकर पूरे राज्य में कोऑपरेटिव और स्टेकहोल्डर्स के लिए कैपेसिटी-बिल्डिंग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आइजोल, कोलासिब और मामित ज़िलों की अलग-अलग कोऑपरेटिव सोसाइटियों के 90 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

नेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन ने युवाओं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने को लेकर पांच दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें 11 राज्यों से 53 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। एनसीयूआई की डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव श्रीमती सावित्री सिंह ने सामाजिक-आर्थिक विकास में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

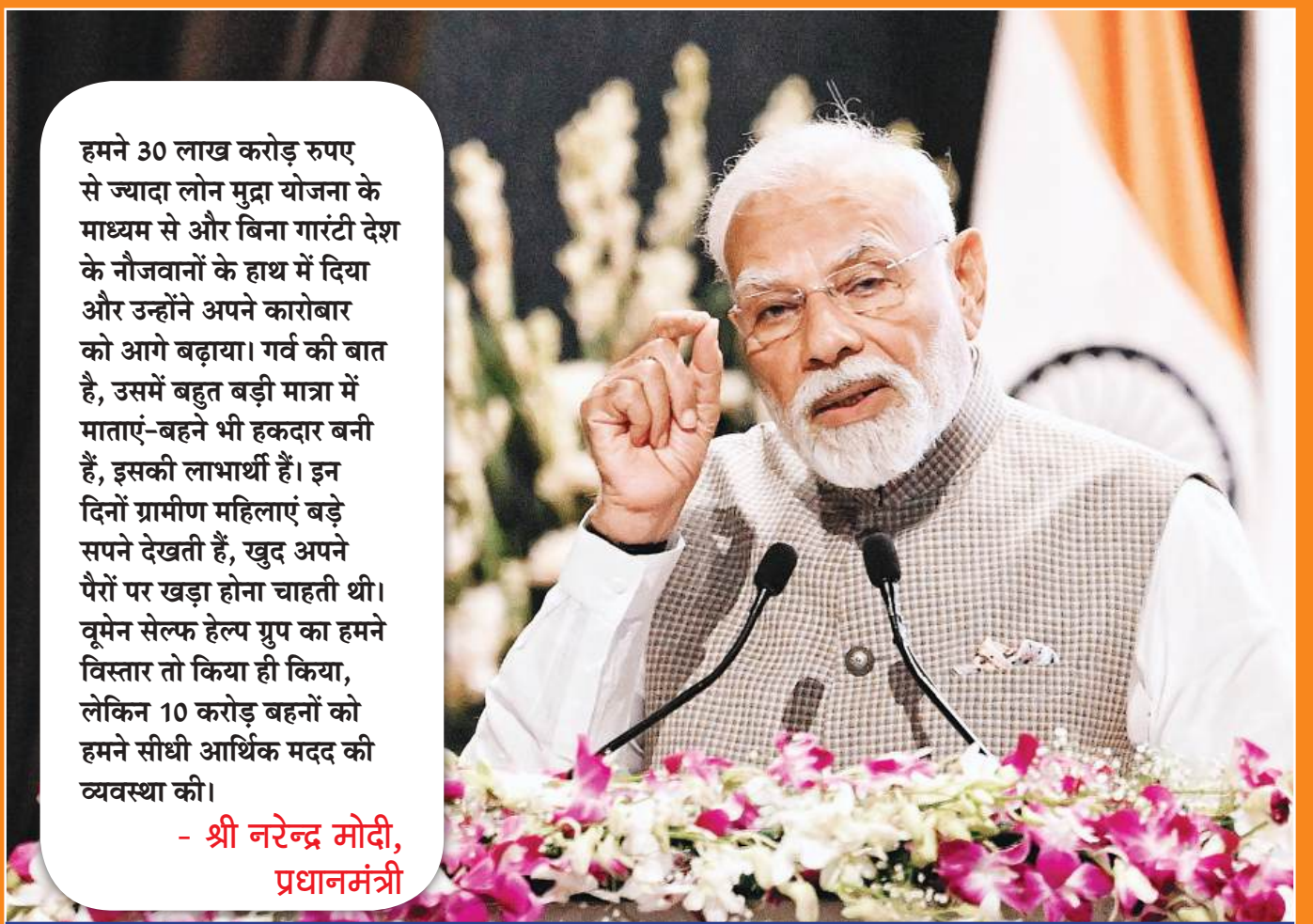

हमने 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोन मुद्रा योजना के माध्यम से और बिना गारंटी देश के नौजवानों के हाथ में दिया और उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। गर्व की बात है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में माताएं-बहने भी हकदार बनी हैं, इसकी लाभार्थी हैं। इन दिनों ग्रामीण महिलाएं बड़े सपने देखती हैं, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमने विस्तार तो किया ही किया, लेकिन 10 करोड़ बहनों को हमने सीधी आर्थिक मदद की व्यवस्था की।

- श्री नरेन्द्र मोदी,
प्रधानमंत्री

एनसीयूआई हाट, एनसीयूआई और कम प्रचलित सहकारी संस्थाओं के बीच नये आयाम स्थापित कर रहा है, जो उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। अब एनसीयूआई हाट अपने नवीन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी *'सहकार से समृद्धि'* को साकार करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण कर रहा है।

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (CEAS-LMS) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिर्सोस सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

HINDI

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक : राजीव शर्मा

RNI No: DLHIN/25/A0141
Published on 21.03.2026 Postal Registration No: DL-SW-01/4214/2023-24

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ